THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Dr. John Brittas, please listen. I know the rule. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं और मुझे सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... जब प्वाइंट ऑफ ऑर्डर होता है। देरेक साहब, कृपया बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए। मैं आपको समय दूंगा। रेलवे बजट पर चर्चा समाप्त हुई। ...(**व्यवधान**)...

SOME HON. MEMBERS: No, no. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: This was Discussion on the Working of the Railways. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मुझे यह पता है कि रेलवे की वर्किंग पर चर्चा हुई थी, वह समाप्त हो गई है और चर्चा समाप्त होने के पश्चात् आपने केवल इस बात पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय मंत्री जी ने बजट शब्द का प्रयोग कर दिया था। रेलवे के कार्य पर चर्चा हो रही थी, अब वह समाप्त हो गई है। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने दूसरा बिजनेस पुकार लिया है। अब General Discussion on Budget प्रारंभ होगा। Shri Pankaj Chaudhary.

THE BUDGET (MANIPUR), 2025—26
AND
GOVERNMENT BILLS

I. **The Appropriation Bill**, 2025
II. **The Appropriation (No.2) Bill**, 2025
III. **The Manipur Appropriation (Vote on Account) Bill**, 2025
IV. **The Manipur Appropriation Bill**, 2025

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY): Sir I move:

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fundof India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2022, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2024-25, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of a part of the financial year 2025-26, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of the financial year2024-25, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The Budget (Manipur), 2025-26; The Appropriation Bill, 2025; The Appropriation (No.2) Bill, 2025; The Manipur Appropriation (Vote on Account) Bill, 2025; and the Manipur Appropriation Bill, 2025 are now open for discussion. I will now call the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Shaktisinh Gohil.

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात) : महोदय, उन्हें एक मिनट दे दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I have already listened to it. *...(Interruptions)...*

श्री शक्तिसिंह गोहिल : वे बहुत सीनियर मेम्बर हैं। ...(**व्यवधान**)... हाउस ऑर्डर में होगा, तो ठीक चलेगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : देखिए, रूल्स में प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य, मैंने अगला बिजनेस पुकार लिया है, मैं अब पीछे नहीं जा सकता हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, please understand what is happening in the House. *...(Interruptions)...* I will explain it to you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): It is impossible now for me to go back as I have called the next Business. ...*(Interruptions)*... मैं आगे निकल गया हूं। माननीय सदस्य, सदन पीछे नहीं जा सकता है। ...(**व्यवधान**)... शक्तिसिंह जी, आप अपना भाषण प्रारंभ कीजिए। ...(**व्यवधान**)... No, I am unable to do it. ...*(Interruptions)*... शक्तिसिंह जी, आप अपना भाषण प्रारंभ कीजिए, अन्यथा मैं नेक्स्ट पुकारूँगा।

श्री शक्तिसिंह गोहिलः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज Appropriation Bill, 2025 और Manipur Appropriation Bill, 2025 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं सबसे पहले मणिपुर का vote on account और मणिपुर का जो Appropriation Bill बिल आया है, उस पर बात रखूंगा। मणिपुर के बजट के जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, सरकार ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, अगर हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को देख लें, तो सत्य मालूम हो जाएगा। महोदय, बाहर यह कहा जाता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब चंगा सी, सब ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फिगर दिखाना चाहूंगा।

महोदय, मणिपुर एक छोटा राज्य है। यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, वहाँ पर भी वही सरकार थी और उसने जो बजट रखा था, उनका 2024-25 का जो बजट एस्टिमेट रखा गया था, उसके बाद उन्होंने Revised Budget रखा। महोदय, जो आज की फिगर्स दिख रही हैं, बजट और रिवाइज्ड बजट के बीच में सरकार की जो revenue receipt होनी थी, वह 3 लाख, 34 हज़ार, 223 रुपये, figure in lakhs, 3 लाख, 34 हज़ार, 223 सरकार का revenue, जो expected था, वह Revised Estimates में कम करना पड़ा। यानी, जब सरकार की इतना बड़ी आवक कम हुई है, तो इस सरकार को इस बात से चिंता होनी चाहिए कि जब स्टेट की इन्कम आपके बजट से, रिवाइज्ड बजट में इतनी कम हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है और हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री शक्तिसिंह गोहिल : महोदय, मैं यह जरूर कहूंगा कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, हमारे पोलिटिकल इंटेरेस्ट को छोड़कर नेशनल इंटेरेस्ट को ऊपर रखना होगा। अगर देश एक न रहा, अगर देश के अंदर हर कोने पर हम यह मैसेज नहीं दे पाएं कि सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का जमीर भी हमारे साथ है और हमारा जमीर भी उनके साथ है, हमारा दिल भी वहाँ है, तब यह देश एक नहीं रह सकता। महोदय, क्या हम देश के हित में अपने पोलिटिकल इंटेरेस्ट साइड में नहीं रख सकते?

महोदय, जब यह देश आज़ाद हुआ था, तो पूरी दुनिया कहती थी कि यहाँ इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे मज़हब, इतनी सारी कास्ट्स और इतने सारे लोग हैं, इसलिए आज़ादी के बाद यह देश एक नहीं होगा, इसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। यह कहने वाले लोग दुनिया भर में थे।

4.00 **P.M.**

हमें नमन करना चाहिए कि आजादी के बाद जो हमारे पूर्वज आए, जिन्होंने शासन चलाया, जिन्होंने देश चलाया, इस देश को एक और अखंडित रखा। आज हम क्या करते हैं? मणिपुर के लोगों को कब यह एहसास होता कि पूरा देश उनके साथ है, जब हमारे प्रधान मंत्री वहां जाकर उनके दुख में हिस्सा लेते, उनके दर्द को महसूस करते। इसके साथ हम सब पार्लियामेंट में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर में लोगों की दिक्कतों के लिए एक आवाज में चर्चा करते और unanimous resolution पास करते कि मणिपुर का दर्द कोई मणिपुर स्टेट का नहीं, बल्कि पूरे देश का है और पूरा देश आपके साथ है। क्या हम यह नहीं कर सकते थे? अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस पर चर्चा कर सकती है, अगर यूरोप की पार्लियामेंट में चर्चाएं हो सकती हैं, अगर दुनिया के देश इसकी चिंता कर सकते हैं, तो हमें क्यों चिल्लाना और लड़ना पड़े कि हमारे देश की पार्लियामेंट में, हमारे देश के राज्य मणिपुर की चर्चा होने दो? इसके लिए हमें क्यों लड़ना पड़े? मैं सरकार से यह उम्मीद जरूर करता हूं कि वह इस बात को सिर्फ पॉलिटिकल आस्पेक्ट से नहीं ले, बल्कि सही मायने में ले।

सर, हम देखते हैं कि वहां इतने महीनों तक दिक्कतें रहीं। मणिपुर में सैकड़ों जाने गईं। हम कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और वहां उन मां-बेटियों की हालत देखकर अगर पत्थर दिल इन्सान भी हो, तो उसकी भी रात की नींद हराम हो जाए। हमने वहां उस तरह की परिस्थिति देखी। 60,000 लोग बेघर हो गए, तो कल्पना तो कीजिए कि उस राज्य में उन लोगों की हालत क्या होगी? सर, यह ऐसा राज्य है कि जहां पर इतनी दिक्कतों के बाद जब राहुल गांधी जी वहां पर न्याय यात्रा लेकर निकले, मैं भी वहां गया हुआ था - मैं वहां के लोगों के दिलों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं कि वे इतनी दिक्कतों के बाद भी प्यार से हमारा वहां पर स्वागत करने के लिए खड़े थे। मैं प्रधान मंत्री जी से कहता हूं कि लीडर ऑफ दि अपोजिशन गए और आप भी जाकर देखिए।

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

नमस्कार, सर। Sir, I am very happy to see you here in the Chair when I am speaking. आप जल्दी से बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएं। यह मैं अपनी पार्टी और निजी तौर पर आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां 21 महीने से दिक्कतें चल रही थीं और मणिपुर के इस बजट में 2,866 करोड़ का जो बजटरी एलोकेशन है, यह किसके लिए दिया है? A budgetary allocation of Rs. 2,866 crore for 2025-26 has been made towards incentives for police personnel posted in sensitive areas. ये वहां के लोगों के अधिकार के पैसे हैं। भारत सरकार को ये पैसे स्पेशली देने चाहिए। वहां के बजट से हमें नहीं लेने चाहिए। हमें उन लोगों से ये पैसे नहीं लेने चाहिए।

सर, relief and rehabilitation वहां के लोगों की अहम मांग है। मैं बजट डॉक्युमेंट्स को देख रहा था। सिर्फ 15 करोड़ दिए गए हैं। ये किसके लिए दिए गए हैं - for temporary shelters; Rs. 35 crore towards housing displacement; Rs. 100 crore for relief operations. Is it enough? क्या हम इससे संतुष्ट हो सकते हैं? जब 60 हज़ार लोग बेघर हुए हैं, जब सैकड़ों जानें

गई हैं, जहां डिस्ट्रेस है, वहां हमें उदारता दिखानी चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी वहां राज कर रही थी। शासन आता है, शासन जाता है। हमें हमारी political power जनता जनार्दन देती है और हमारा अहम काम उन्हीं लोगों की सुरक्षा और हित है। यह डेमोक्रेसी में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

सर, मैं मणिपुर का Budget at a Glance देख रहा था। Revenue Expenditure, 61 per cent; Capital Expenditure, 39 per cent. आप कौन से विकास की बात करते हैं! जब आपका 61 परसेंट बजट सिर्फ तनख्वाह और आपके दूसरे कामों में जाता है, जहां से कोई asset नहीं बन रही है। आप उसको सिर्फ 39 परसेंट planned budget में दे रहे हैं। कैसे मणिपुर का विकास होगा!

मैं मनरेगा की बात भी देख रहा था। मणिपुर में 2023-24 में 50 परसेंट मनरेगा का फंड release नहीं हुआ है। क्या हमें चिंता नहीं होनी चाहिए? There are concerns about Manipur's economical stagnation. सर, पूरे देश में कम per capita income वाले राज्यों में मणिपुर आता है। अगर हम Gross State Domestic Product (GSDP) की बात करें, तो यह stagnant हो रखी है। क्या हम इस राज्य के लिए भारत सरकार की ओर से कुछ ज्यादा उदार नहीं हो सकते थे? हमारी प्रसिद्धि के लिए आप economic measures ले लीजिए, मंत्रियों के खर्चे में भी थोड़ी कमी कर लीजिए, आप हमारी भी तनख्वाह थोड़ी काट लीजिए, पर मणिपुर के लोगों की चिंता करिए, मैं यही कहना चाहता हूं। मणिपुर के लिए जो allocation हुआ है, मैं जरूर इस बात से चिंतित हूं।

अभी मणिपुर में बहुत बड़ी flood आई। मैं जानता हूं, मैं बिहार का प्रभारी रहा हूं। बिहार में भी flood management के लिए यह जरूरी है। जहां चुनाव आता है, उस वक्त उस राज्य की तो बड़ी ज़ाहिरात, बड़ी publicity, बड़े allocation का नाम होता है, फिर उस स्टेट को भी मिलता तो नहीं है। उसी तरह आपने बिहार के लिए बजट में 11,500 करोड़ की announcement की। I hope कि मिले, पर मणिपुर में जो जरूरत है...

श्री सभापति : शक्तिसिंह जी, एक सेकंड। प्रभारी का मतलब क्या होता है?

श्री शक्तिसिंह गोहिल : सर, पार्टी की ओर से in-charge. I was in-charge for Bihar.

MR. CHAIRMAN: I wanted to be clear. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: And that is why I know कि बिहार को water management की बहुत जरूरत है। कुछ areas में flood भी आती है। ...(**व्यवधान**)... जी, आप भी थे, उसी पार्टी से थे।

श्री सभापति : रमेश जी, जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शक्तिसिंह गोहिल : सर, वहां 11,500 करोड़ की announcement हुई है। वह तो पहले कितना दूं, कितना दूं भी हुआ था, लेकिन मिला कुछ नहीं था। पर मणिपुर के लिए, flood से जूझ रहे उस मणिपुर के लिए कुछ प्रावधान करने की बहुत आवश्यकता थी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी गुजरात से आते हैं। मैं बहुत करीब से जानता हूं। सभापति महोदय, आपके जरिए मैं जरूर प्रधान मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि गांधी जी भी गुजरात से थे। एक गरीब के घर में दिक्कत होती थी, तो third class के डिब्बे में बैठ कर वे वहां पहुंच जाते थे। प्रधान मंत्री जी, आज आप मणिपुर जाइए। हमारा गुजरात गांधी का गुजरात है, जहां की यह परंपरा है कि एक दुखी होता है, तो सत्ता में बैठे हुए आदमी की आंख में आंसू आना चाहिए। यह गांधी मॉडल गुजरात का है, उसी को नजर में रखिए। आपके लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी विश्व में इतने बड़े लीडर हैं कि यूक्रेन और रूस का war रुकवा सकते हैं और वे ही रुकवाएंगे। कुछ सोशल मीडिया में अंधभक्त कहते हैं कि पापा ने war रुकवा दिया, पापा ने war रुकवा दिया। मैं कहता हूं कि आप मणिपुर में शांति करवा दीजिए। यूक्रेन और रूस के war रुकवाने की जगह जरूरत यह है कि आप वहां जाइए, लोगों के बीच जाइए। मैं कहता हूं कि वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल गांधी जी वहां गए, लोगों ने प्यार दिया। डरने की जरूरत नहीं है। मणिपुर हमारा है, बहुत प्यारा है और वहां के लोग तो बहुत बढ़िया हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी वहां जरूर जाएं, यह मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, जो दो Appropriation Bills आये हैं, अब मैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। हमारे संविधान के Article 115 में इसके बारे में provision है। हमारे संविधान ने बहुत बढ़िया तरीके से financial control पार्लियामेंट को दिया है और पार्लियामेंट का financial control सरकार के ऊपर रहता है। आप Article 115 के तहत Appropriation Bills लेकर आए हैं। मैं पहले यही बात करता हूँ कि क्या आपकी इस सरकार में financial discipline है? अगर यह होती, तो जो आंकड़े मिल रहे हैं - एक लाख करोड़, which was provided in Budget. You did not spend Rs. 1 lakh crores. क्या यह financial discipline है?

दूसरी बात, मैं समझ सकता हूं कि आपने एक 'x' amount लगाई और आपको कोई संयोग आ गया कि खर्च ज्यादा करना पड़ा, तो the Constitution has provided in Article 115 to go before the Parliament and once Appropriation Bills are passed, your expenditure will be regularized, परन्तु आप figures तो देखिए। आप 2022 का Appropriation Bill आज लेकर आए हैं। आप कौन से sector में लाये हैं, क्या आपने देखा? मैं इसका विरोधी नहीं हूं। जरूरत पड़ने पर बजट के बाहर जाकर भी खर्च कीजिए, परन्तु पार्लियामेंट में इसे justify कीजिए। जब बात होती है, तो मंत्री जी का जवाब आएगा। वे जेएनयू में पढ़ी हुई मंत्री जी हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं। देखिए, मेरे नाम लेते ही वित्त मंत्री जी आ गईं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई वित्त मंत्री जी हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि political observation नहीं, कुछ चीजें हैं, * आप प्यार से कहें, वह मैं आपके जरिए जरूर मंत्री जी को कहना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: Shaktisinh*ji*, I would look into this observation.

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sorry, Sir.

---

* Not recorded.

श्री सभापति : गुस्से वाली बात अच्छी नहीं है।

श्री शक्तिसिंह गोहिल : मैं तो उनसे इसकी उम्मीद नहीं रखता हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। The entire nation will be proud.

SHRI SHAKTISINH GOHIL: With her smiling face, we can see a glorious woman here. वे बहुत अच्छी लगती हैं। हमें तो उनको देख कर प्रेरणा मिलती है। *

श्री सभापति : यह भी delete कर दिया जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल : परन्तु मैं उस यूनिवर्सिटी की इज्जत करता हूं। मैं यह कहना चाहता था कि वित्त मंत्री जी जरूर यह कहेंगी कि संविधान ने तो मुझे तीन-तीन बार Appropriation Bill लाने का अधिकार दिया है, लेकिन self-restriction है कि मैं दो बार ही लेकर आती हूँ। आप लाइए, परन्तु मैं आपसे यह कहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट आपके पास additional expenditure करने के बाद Appropriation के लिए आते हैं, तो माननीय सभापति जी, मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए या उनके expenditure की जांच कीजिए। आपके Appropriation Bill में हमारे डिफेंस के additional expenses आए। इसमें कोई विरोध नहीं है। डिफेंस में हमारे जवानों के लिए जितना खर्चा करना है, वह कीजिए। वे हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, उनके लिए जितना खर्चा करना चाहिए, वह कीजिए। परन्तु वहाँ क्या हो रहा है? Comptroller and Auditor General ने देखा कि हमारे उन जवान फौजियों के लिए expiry date वाला सामान दिया जा रहा है। जब वह बात उठती है, तो as Finance Minister, आप उनको थोड़ा tight कीजिए कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप C&AG का वह Audit Para तो देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है? जिनको उस height पर, उस ठंड में रहना है, अगर उनके लिए डीजल नहीं है, उनके लिए केरोसीन नहीं है और उनको बर्फ में चलने के लिए जो जूते चाहिए, वे उनको गलत तरीके के मिल रहे हैं, तो हम खर्च कितना भी करें, परन्तु वह सही जगह पर जाता है या नहीं, वह देखा जाए।

सभापति महोदय, आयुष्मान की बहुत बात होती है। मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि आयुष्मान की बात होने के बाद, इस पर जो खर्च होता है, उसके बारे में मैं तीन दिन पहले की इसी की एक individual बात जरूर करना चाहूंगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एसवीपी अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ। वह कच्छ का था। जब वह एडमिट हुआ, तो उससे पूछा गया कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? उसने कहा, हाँ है, तो उसे कहा गया कि आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वह एडमिट होता है, उसकी treatment शुरु होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी पांव काटनी पड़ेगी। जब वह वहीं किसी दूसरे डॉक्टर को अपना prescription दिखाता है, तो वे कहते हैं कि less circulation of blood है, stent लगा देने से

* Not recorded.

circulation हो जाएगा, पांव काटने की जरुरत नहीं है। उसके बाद वह कहता है कि मुझे अस्पताल से छुटटी दे दो, क्योंकि मुझे अपनी पांव नहीं कटवानी है। उस पर उसको कहा जाता है कि नहीं, पैंतीस हजार रुपए भरो। उसके बाद उसने कहा कि आपने कहा था कि आयुष्मान कार्ड होने पर पैसे नहीं देने होंगे। इस पर उसको कहा गया कि यदि आप पांव कटवाओगे, तो free treatment और यदि इलाज आधी छोड़ कर जाना है, तो पैंतीस हजार रुपए भरने पड़ेंगे। मैं patient के नाम के साथ डिटेल देता हूँ। क्या यह आयुष्मान का काम है? मैं वित्त मंत्री जी की मंशा पर कोई doubt नहीं करता हूँ। In our State, I was also Finance Minister. When the department comes to us, it is our duty to face the Assembly or Parliament. पर, जो department यह किया है, उस department को यदि उनके मंत्री नहीं कहते हैं, तो hon. Finance Minister उसे tight कर सकती हैं। जहां यह चल रहा है, वहाँ आप अपनी उस power को यूज़ करके ऐसा कर सकती हैं।

सर, 'मनरेगा' के लिए allocation होता है, extra budget की बात आती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ and I will send the copies of those newspapers where the journalists have done some investigative journalism. 'मनरेगा' में क्या होता है? उसमें मरे हुए आदमी का नाम है। उसका पैसा कहीं और चला जाता है। अभी दाहोद का मामला आया है, जिसमें contractor के नाम पर करोड़ों रुपए का बिल है। मजदूर के accounts खुलवा कर उनका ATM cards अपने पास रखते हैं और सीधा पैसा उनके पास जाता है। गुजरात में सीबाआई से investigation करवाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसमें यह पता चलेगा कि कितना पैसा गरीब को मिलता है और कितना पैसा बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल हैं। स्टेट की पुलिस के द्वारा या स्टेट के किसी एजेंसी के माध्यम से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इसमें या तो ज्यूडिशरी मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा या यह होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। We are the treasurers of the Government money. हम लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, जनता का पैसा जनता के हित के लिए खर्च हो - यही हमारा काम है। इसके लिए जो Appropriation Bill आया है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि आज financial discipline की जरूरत है। ...(**समय की घंटी**)... आज इसे देखने की जरूरत है।

महोदय, आपने मेरी पूरी स्पीच को बड़े प्यार से, प्रोत्साहित करते हुए बिना रोके-टोके सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर आ गई हैं, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade; fifteen minutes.

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आपकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप आज आए, तो पूरा सदन हंसी से खिल उठा है। हम सभी सब आपकी लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। हमारे सदस्य जी ने विपरीत दृश्य बताने की बात की है। सच तो यह है कि मणिपुर एक देवभूमि है, स्वर्ण भूमि है। मणिपुर राज्य हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। मणिपुर को 'sana leibak' कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यह स्वर्ण भूमि है। इसको 'ला लै बाक' कहते हैं, यानी

देवभूमि कहते हैं। यहाँ 'भारत जोड़ो' की बात की गई, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 'भारत जोड़ो' की बात करने वाले अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग क्यों करते हैं? अगर सच में आपको मणिपुर से प्रेम है, तो आप विपरीत दृश्य बताने की बजाय उस मणिपुर के ऊपर solution दीजिए।

माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणिपुर राज्य की सारी महिलाएं आर्थिक प्रगति में बहुत आगे बढ़ रही हैं। एशिया में यहां पर महिलाओं का सबसे बड़ा मार्केट है और उसका नाम 'इमा मार्केट' है । यहां पर सामान बेचने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है, पुरुषों को नहीं है। वहाँ जो वस्तुएँ होती हैं, जैसे धान, फ्रूट्स, सब्जी आदि हैं, इन सब वस्तुओं को सिर्फ महिलाएँ बेचती हैं। वहां की आयु रेखा बहुत बड़ी है। सूरज की किरणें वहां सुबह 3 बजे आती हैं और सूर्यास्त भी जल्दी होता है। मैं मानता हूं कि मणिपुर एक ऑर्गेनिक स्टेट है, मणिपुर में धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहर है, मणिपुर की कृष्ण और राधा की रासलीला एक अंतरराष्ट्रीय हेरिटेज बन चुकी है। मणिपुर को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मैं यह चाहता हूं कि यह प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति हमेशा बनी रहे। प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से मणिपुर को जो मदद की है, उसमें खेलकूद में मणिपुर आगे बढ़ रहा है। वहां माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वहां की सरिता देवी, नीलकमल, कुंजारानी, मेरीकॉम, बाला देवी जैसी 30 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हमारा नाम बढ़ाया है, इसलिए मोदी जी ने 2018 में मणिपुर को एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आंकड़े भी बताना चाहता हूं कि वहां पर वर्ष 2021 में 317 करोड़, 2022 में 213 करोड़, 2023 में 467 करोड़, 2024 में 543 करोड़ की राशि आवंटित की गई और 2025 में अनुमोदित राशि 987 करोड़ है। यहां पर हमेशा विपरीत दृष्टि बताई जाती है। मैं कांग्रेस के अपने साथी को बताना चाहता हूं कि जो वार्षिक बजट है, वह 2014 के पहले 5 साल में सिर्फ 2,122 करोड़ था और 2025-26 में उसको बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको 5 गुना करके 10,440 करोड़ किया है। मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का मन से बहुत आभारी हूं, क्योंकि इन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किये हैं। 6 दिसंबर, 2024 को 28 नए नवोदय विद्यालयों में से तीन नवोदय विद्यालय मणिपुर को दिए गए हैं, जो Thoubal, Kangpokpi और Noney में स्थापित होंगे।

सर, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 7 मार्च, 2024 को उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना लाई गई है। उन्नति-2024 में 10,037 करोड़ की लागत से यह कार्य किया गया है। सर, मैंने अभी आपको राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के बारे में बताया। 2020 में नये आईआईटी, इम्फाल का उद्घाटन किया गया है और उस आईआईटी से हिंदुस्तान के सभी छात्र लाभ ले रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन में इम्फाल को चयनित किया गया है, यह भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर-पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के अंतर्गत मणिपुर में 8 सड़कें और पुल की परियोजनाओं में 375 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहां पर 235 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2,411 करोड़ से भी अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के थ्रू मणिपुर की प्रमुख परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। एमटीयू, जिसे मणिपुर का तकनीकी विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसके माध्यम से

मणिपुर के आईटी के प्रोसेसिंग ज़ोन का विकास किया गया है। वहां एक 60 बिस्तरों वाले मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया है। यहां मणिपुर के राज्य सभा सांसद, महाराजा जी बैठे हैं। इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के नाम से स्थापित धनमंजूरी विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का भी विकास किया गया है।

सर, मैं और क्या-क्या चीज़ बताऊं? मणिपुर में एक ब्लैक मिट्टी मिलती है, जो वहां लोम्पी में होती है, जो कि उखरुल जिले में आता है। वहां की काली मिट्टी में मेडिकल साइंस छुपा है। इस मिट्टी के पॉट में पानी अपने आप फिल्टर होता है। उस पॉट में रखा गया पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है। सब्जी, दही, दूध, खाना, ये सारी चीजें ब्लैक पॉट में रखी जाती हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस चीज को देखा और लोम्पी ब्लैक पॉटरी के प्रचार के लिए इस गांव को कलाकार गांव की संज्ञा दी है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसा ही विजन रहना चाहिए। सड़क और रेलवे का विकास - 2014 के बाद 1,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। भारतमाला परियोजना में 635 किलोमीटर राजमार्ग को 11,102 करोड़ की मंजूरी मिली है। 1,026 किलोमीटर की 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 44 परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में दी गई हैं। यहां पर हिल और वैली को अलग-अलग नहीं समझा गया है। वैली और हिल दोनों को समान रूप से देख कर हिल क्षेत्रों में भी बिना किसी जाति, पंथ या धर्म का भेदभाव किए इन सभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का मन से धन्यवाद देना चाहता हूं।

वर्ष 2016 में मणिपुर को ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ा गया, जो अब जिरीबाम तक पहुंच चुका है। वर्ष 2022 में पहली मालगाड़ी यहां पहुंची, जिसका नाम मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिनल्यू के नाम पर रखा गया। यह मालगाड़ी 2022 में इस रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इम्फाल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो चुका है। रेल मंत्री जी की इस पहल के लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। 'अमृत भारत योजना' के अंतर्गत इम्फाल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसलिए, प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का मन से आभार व्यक्त करता हूं।

पूर्वोत्तर रेलवे बजट आवंटन के संदर्भ में, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस ने पांच साल में मात्र 2,122 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जबकि, हमारी सरकार ने मात्र एक वर्ष में 10,440 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कांग्रेस के मुकाबले पांच गुना अधिक है। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मन से धन्यवाद देता हूं।

'जनधन योजना' के अंतर्गत पूरे भारत में कुल 54 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें मणिपुर का योगदान 11 लाख खातों का है। इनमें 57 परसेंट महिलाएं हैं। 'पीएम मुद्रा योजना' के तहत अब तक 31 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जिसमें मणिपुर को 2,850 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है।

'जल जीवन मिशन' के तहत पूरे देश में 12 करोड़ नल कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें मणिपुर को 3.3 लाख नल कनेक्शन मिले हैं। मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि उन्होंने 'पीएम आवास योजना' के अंतर्गत भारत में 2.68 करोड़ घर गरीबों को उपलब्ध कराए हैं। इसी योजना के तहत मणिपुर में भी बहुत सारे घर गरीब भाइयों और बहनों को दिए गए हैं।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत भारत में अब तक 11.79 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिनमें से मणिपुर में 2.8 लाख शौचालयों का निर्माण प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के सहयोग से हुआ है।

'पीएम उज्ज्वला योजना' के तहत – मैंने मणिपुर की महिलाओं के बारे में भी बोला है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारी महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्ष 1904 में और वर्ष 1929 में यहां की महिलाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए, मैं हमारी मणिपुरी माताओं और बहनों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 10.33 करोड़ लाभार्थियों को देशभर में गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधान मंत्री जी ने 'पीएम उज्ज्वला योजना' लाकर एक सफल प्रयास किया है, क्योंकि मैं खुद महीने में एक बार मणिपुर जाता हूं। मैंने देखा है कि इस योजना के तहत भारत में 10.33 करोड़ लाभार्थी हैं और यहां हमारी ढाई लाख महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी हैं। मणिपुर में 2.5 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। मणिपुर एक छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यहां केवल दो लोकसभा सीटें हैं, परंतु यह देवभूमि है। मणिपुर की संस्कृति, परम्पराएं, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, यहां की प्राकृतिक धरोहर – सब कुछ अद्भुत हैं। विपक्ष के लोग मणिपुर के बारे में जो बातें बोल रहे हैं, वे विपरीत बातें बोल रहे हैं। हमें मणिपुर की अच्छाइयों को दुनिया के सामने लाना है। यहां का ऑर्गेनिक बाजार, फल, सब्जियां विश्व प्रसिद्ध हैं। मणिपुर के लोग ईमानदार, मेहनती और सच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी के हृदय में मणिपुर हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। यहां 'पीएम किसान योजना' लागू की गई, यहां ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रमोट करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने बहुत बड़ा सपना देखा है। यहां के 85,917 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ

[**उपसभाध्यक्ष (श्री प्रमोद तिवारी)** *पीठासीन हुए।*]

मिला है। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का मन से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, यहां पर ऐसा बोला गया है कि मणिपुर को कुछ नहीं दिया गया है। इसमें क्या-क्या नहीं दिया गया है? कर हस्तांतरण, अनुदान सहायता, बुनियादी ढांचा परियोजना, राजमार्ग, रेलवे, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र और निवेश के क्षेत्र में राज्य में अर्थव्यवस्था की मजबूती की गई है। यहां पर अभी मैंने स्पोर्ट्स के विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया है। अभी मेरे मित्र ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में बोला। आयुष्मान भारत योजना में कुल मिलाकर 6 लाख, 47 हजार बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। उनको मेरा कहना है कि सच्ची बातें सदन में रखा करो और सारी अच्छी बातें रखा करो। हमेशा मणिपुर के बारे में एक गलत चेहरा दुनिया के सामने बताना अच्छी बात नहीं है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मणिपुर में 35 लाख एनरोलमेंट हुए हैं। वहां पर पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 55 लाख एनरोलमेंट हुए हैं। यहां पर अटल पेंशन योजना में 63,400 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन में तकरीबन 2.8 लाख हाउसहोल्ड, जो टॉयलेट्स हैं, उसकी बात अभी मैंने की है। मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें कुल मिलाकर 20 लाख बेनिफिशियरी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में काम कर रहे हैं और इसका लाभ मणिपुर की जनता को मिल रहा है। यहां पर बहुत

सारी चीजें ऐसी हैं, जिनको विदेश की मार्केट भी बहुत बड़े प्रमाण में मिल सकती है। मणिपुर प्रदूषण मुक्त राज्य है। यहां पर गर्मी में भी गर्मी नहीं होती है, एयर कंडीशन की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि निसर्ग ने मणिपुर को आशीर्वाद दिया है, इसलिए मणिपुर देवभूमि है। मणिपुर के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और मणिपुर के जंगलों में मणिपुर की जड़ी-बूटियां, मणिपुर का आयुर्वेद, मणिपुर के निसर्ग को आयुष मंत्रालय से जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। अभी यहां महाराजा जी बैठे हैं। वे मुझे रोज पान खिलाते हैं, जिसको मणिपुर में क्वा बोलते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूं, लेकिन जब दो बार उन्होंने मुझे पान खिलाया, तो मेरी पेट की समस्या कम हो गई। मणिपुर में ऐसा आयुर्वेद का भंडार है। मणिपुर की अच्छी-अच्छी चीजें आप दुनिया के सामने लाओ। मणिपुर क्या है, उसके बारे में एक अच्छी चीज़ बताओ। दुनिया में मणिपुर को बदनाम मत कीजिए। मणिपुर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। मैं आप सब लोगों को मणिपुर की और एक खासियत बताता हूं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कमल है। कमल का स्थान हमारे हृदय में है। इससे वस्त्र बनाने का पवित्र कार्य हमारी माता-बहनें मणिपुर में कर रही हैं और मुझे बताने में खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने अपने मन की बात में हमारी इन माता और बहनों का अभिनंदन किया है। यहां की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, यहां के हैंडीक्राफ्ट्स प्रसिद्ध हैं, यहां का ऑर्गेनिक फ्रूट प्रसिद्ध है, विदेशी पर्यटक आकर यहां की सब चीजें खरीद लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव किया ...(**समय की घंटी**)... उसमें मणिपुर का भी उल्लेख किया गया। उसमें हजारों विदेशी पर्यटक आए। भारत मंडपम में मणिपुर की हैंडीक्राफ्ट साड़ी और ऑर्गेनिक फ्रूट का बाजार लगा था, जिसको सारे विदेशी पर्यटक ले गए। यही मणिपुर की खासियत है। प्रधान मंत्री जी इसको ही बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**) **:** अब आप समाप्त कीजिए, क्योंकि समय पूरा हो गया है।

डा. अजित माधवराव गोपछड़े : मणिपुर को बदनाम मत कीजिए। मणिपुर को जोड़ने के लिए आप सॉल्यूशन दीजिए। मणिपुर को जोड़ने की बात कीजिए, उसको तोड़ने की बात मत कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद, थैंक यू।

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**) **:** धन्यवाद, गोपछड़े जी। अब मैं बिकास रंजन भट्टाचार्य जी से आग्रह करूंगा। आपका पांच मिनट का समय है। ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: What about Ms. Sushmita Dev? ***...(Interruptions)...***

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**)**:** इसके बाद।

SHRI DEREK O'BRIEN: Why?

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**) **:** सीरियल में है। ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is the basis? ...*(Interruptions)*... No; what is the basis? ...(Interruptions)... We have 13 MPs. What is the basis? ...*(Interruptions)*... We are 13 Members of Parliament? ...*(Interruptions)*... What is going on? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRAMOD TIWARI): I will tell you ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir; we have to follow the rules. This is the 'Rules of Parliament.' ...*(Interruptions)*... What is going on? ...*(Interruptions)*... What is the problem? ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**): बिकास जी की रिक्वेस्ट आई थी, उसके अनुसार उन्हें पहले बोलने का मौका दिया गया है। सामान्यतः जब कोई सदस्य किसी कारण से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें अवसर दिया जाता है। बिकास जी, आप बोलिए।

SHRI BIKAS RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me time. But the point is, what prompted the Manipur Budget to be placed in the Parliament? We talk about being the 'mother of democracy', but democracy has been shattered when you find that the Indian Parliament has to take up the Appropriation Bill for Manipur. Our Prime Minister has given a new theory, that of 'double-engine *sarkar*'. अब डबल इंजन सरकार धीरे-धीरे एक इंजन सरकार बन रही है या हम पीछे चल रहे हैं? Are we going on reverse gear? And we are talking loudly of this thing and that thing! Manipur was the first place where Netaji Subhash Chandra Bose came with INA for India's Independence and that was really a historical event. Now, this Manipur, which was known to the people as a State of religious amity, a State of brotherhood, has been destroyed by the BJP Government over the last few years. If you go there, you would be shocked to see the reality of what has happened there. The schools have been destroyed. The missionary schools have been destroyed. The two communities are now standing face to face like in a war. This is the contribution of the Government there. And now, the double engine having failed there, you come back to the Parliament and speak aloud that the Prime Minister has done such a beautiful thing there. [£]Now, because of this misrule and governance, the Manipuri people are in such a position that they cannot sit with each other; they cannot talk with each other. They think that they have been deprived of the basic democratic rights given by the Indian country. And they have started asking, 'Modiji, do you think

[£] Expunged as ordered by the Chair.

we are a part of India or not?' I, of course, thank you, Mr. Prime Minister that you did not go there. £You talk in terms of religion; you talk in terms of community; you do not talk in terms of the unity of the Indian people. Therefore, it is good that the Prime Minister has not gone there. Now, the resultant effect is, you come to the Parliament with the Appropriation Bill for Manipur. What is the allocation for education? All these institutions have been destroyed and brought down to the ground by the miscreants, absolutely on the encouragement of forces spreading religious disunity. You talk in terms of religion. You do not talk in terms of the Indian people's amity and fraternity. You talk in terms of the values which were not really part of our Constitution. And, we now have the Manipur Appropriation Bill before us in Parliament. I would like to tell you, Sir, that whatever allocation they may make, it would not bring back peace for the Manipuri people ultimately. To bring back peace for the Manipuri people, let us inculcate the culture of fraternity, let us inculcate the culture of dignity of people and go forward towards building unity. Let them feel that they are a part of India; they are not alien. You have made them feel that they are alien. Now, we have to ultimately pass this Appropriation Bill, but will it really give them benefits which the Indian Constitution enshrines? Does it give the benefit of Indian unity? Let the people there feel that they have a Government which can take care of them. Now they are thinking that they will have a separate administration. Who has prompted them to think like this? It is only the BJP Government. When the situation was normal, you have made it worse. You did not take any step. Now, imposition of President's Rule is not good for the Indian democracy. Your double-engine Government has failed. Therefore, do not speak of double-engine Government again. Rather, think of concentrating on decentralization of power and giving everybody equal power in terms of their strength and in terms of their own culture, education, language, etc. Don't try to impose anything from Centre. That would really break the country. We would appeal, while considering the Appropriation Bill, let the Manipuri people feel, without them being *Meiti* or *Kuki*, that they are Manipuri and a part of India, the great country where Netaji Subhash Chandra Bose had landed. With these few words, I conclude, Sir. Thank you for giving me time.

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर, ...(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रमोद तिवारी) : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आपने जो कुछ बोला है, वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। सुष्मिता देव जी।

£ Expunged as ordered by the Chair.

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir, today the debate is a very novel experience for me for the reason that we are debating the Appropriation Bills regarding the Union Budget and, at the same time, we are debating the General Budget of the State of Manipur. सर, सच पूछिए, तो मैं थोड़ा नर्वस थी कि दोनों को कैसे कम्बाइन करूं? How to get my head around the figure? But in the last 10 minutes, I am feeling slightly more confident about this speech because if a Member of the Council of Ministers can mistake a debate on a 'Ministry' with 'Budget', then, I am sure that this House will give me some leeway.

Hon. Finance Minister is amongst us; I am happy to see that. As regards to Union Budget, an additional spending of about Rs.6,78,508.10 crores for 2025-2026 with 52 Grants and 3 Appropriations passed in the Lok Sabha, have come to the Rajya Sabha and have to be returned from here. The backdrop is grim and I would not like to repeat all the points that various Members of the Opposition have already stated in the discussion on the General Budget. I am sure that the entire nation knows what the state of affairs is when it comes to household savings, food inflation, income inequality, share of manufacturing, unemployment, etc., and the value of the rupee. This Government has kept us all very busy in slogans. There is one particular slogan about which, I think, every Member will speak and the hon. Member, who spoke just before me, also spoke about it. It is coined by none other than the BJP; it is aggressively used by none other than the hon. Prime Minister and the Ministers of the Government of India. It is 'double engine'. What does the word 'double engine' means in a campaign in a State Legislature? I do not know. But I can give a plethora of examples, and this is my view that 'double engine' comes as an intimidation to the people of the State. If you want the desired rate of progress in your State, then please do vote for the BJP because the BJP is in the Centre. That is how the term 'double engine' has been coined. You may say that this is a bald allegation; it is not relevant to a debate on Supplementary Grants but I will try my best to justify myself. In the case of Bengal, we hear all the Ministers constantly targetting Bengal. You have heard our hon. Members of Parliament representing Bengal repeatedly saying that Rs.1.7 lakh crores under various Heads from the Centre are pending for the State of Bengal -- Rs.7,000 crore of NREGS depriving 59 lakh workers and Rs.8,000 crore of Awas Yojana. I am very relieved that it is the Standing Committee, none less than the Standing Committee, which, at page 63, para 3, strongly recommended the release of NREGS funds to Bengal. It is strongly recommended. While expressing its disappointment for no increment in the Budget for NREGS, they have called NREGS a social security that actually helps in giving 100 days of employment to people who wish to work, but do not have employment. I want to tell the hon. Minister that you

talk about irregularities, but the NREG, which is an Act and not some ordinary scheme, in Section 27, does put some duty upon the Government of India. What is that? It states that if there is an irregularity, you can investigate, you can institute an inquiry, you can send a team, look at it, but it is incumbent on the Government of India to institute proper remedial measures for proper implementation within a reasonable period of time. Since the last Assembly election, this is pending. There is a case pending in the High Court, but the Government of India is refusing to solve this problem. This is not an attack on the hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee; this is a direct attack on the people of Bengal, and I once again appeal that on humanitarian grounds, please release this fund. Today, my colleague, Shri Ritabrata Banerjee, has already stated. It is not just about Bengal today. I feel compelled to speak for Tamil Nadu and Kerala also, where their Railway Budgets have been consistently cut, and the figures are in my hand, but it has already been stated. This is another example of saying, अगर डबल इंजन नहीं होगा, तो पैसा नहीं मिलेगा। This is a [£] of federalism. This is an insult to our Constitution and our electorates who have repeatedly shown that they vote one way in the Panchayat; they vote another way in the Assembly; and, they chose to vote another way in the Lok Sabha. Every Chief Minister must accept it and every Central Government must accept it. जो डबल इंजन बीजेपी की सरकार चल रही है, मैं उनको बता दूँ कि even they have not been spared. From what? From cess. The Finance Commission has repeatedly said, please do away with the practice of increasing cess and surcharges for the simple reason that it adversely impacts the divisible pool of taxes. It is a less transparent way and the States do not get an allocation from it. But, till today, the Government of India is blind to those recommendations. So, your double engine, where you have BJP Chief Ministers, I speak to them and appeal to their conscience that you may think that you are one of the drivers in the State, but actually, you are not driving that second engine.

Now, I come to Manipur. मणिपुर के लोगों ने तो देश के प्रधान मंत्री को दो-दो टर्म डबल इंजन सरकार दी। 2017 में दी, 2022 में दी और 2022 में absolute majority में दी। पर आज what happened? What has this double engine *sarkar* given to the people of Manipur? सर, मैं तो मणिपुर एक बार नहीं, हजार बार गई हूँ। मेरे क्षेत्र के पास में ही मणिपुर का बॉर्डर है। मैंने अपनी आँखों से जो देखा है, वह मैं बोलती हूँ कि Manipur is burning, and I appeal to the hon. Finance Minister of India that today -- what we expected for our neighbouring State, which is called 'jewel of India' -- you will not give us a run-of-the-mill Budget. We do not want a run-of-the-mill Budget. It was a golden opportunity for the Prime Minister Modi to vindicate himself and I had introduced that

[£] Expunged as ordered by the Chair.

idea in the Parliament saying, "Give them a package." Today, I will not say that there are no allocations for Manipur. That would be lying. It is documented. Today, what are they saying? They are saying that we will give you Rs.500 crores in the Contingency Fund. Contingency Fund is for unforeseen circumstances or situations which the Assembly has not approved. सर, मैं आपको सिर्फ एक आँकड़ा देती हूँ। And, I request the Minister to reconsider this. Internet shutdowns in Manipur alone have been for 212 days; 5,088 hours out of the total of 7,812 hours nationwide. What is the estimated loss? I am not saying this. Independent NGOs and reports are saying that the total loss to India is 585.4 million dollars, and 60 per cent of the Internet disconnect was in Manipur. So, let us make an estimate on what the loss is. The Government has said that it will give you PM-SHRI funds of about Rs.750 crores. I thank you for giving that.

But, Sir, जो schools पीएमश्री में apply करने के लिए compete करते हैं, उनको portal में log-in करना पड़ता है। उसके लिए internet connection की जरूरत होती है। And, what did we see? We saw students who were studying outside Manipur could not receive even money transfers. What did we see? We saw that because of lack of internet, e-commerce even suffered. Today, Madam Finance Minister is talking about CRF funds. For 66 days of blockade of NH 2 and 37, what is the estimated loss? It is 1,700 crores of rupees. Rs.250 crore is the allocation that has been given. Hon. Minister may like to enquire into this.

सर, आप रोड बनाइए। हम उसका स्वागत करते हैं। हम सड़कों का स्वागत करते हैं। मैडम, रेलवे लाइन बनाइए, we want that, but I want to ask you कि जो लोग सीना ठोक कर 'Act East' कहते थे, मणिपुर के मामले में तो यह 'Act Least' हो गया। उधर यह 'Act Least' हो गया। मणिपुर 22 महीने जलता रहा। एक सदस्य स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। वे 700 करोड़ की बात कर रहे थे। मुझे इस स्मार्ट सिटी को देखने का मौका 2023 के दंगों के बाद मिला, क्योंकि हमारी नेता ममता दीदी ने पहला डेलिगेशन मणिपुर में 2023 के जुलाई महीने में भेजा। उस समय वहाँ सन्नाटा था। उस शहर में सन्नाटा था, वहाँ लोग नहीं थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। आप इमारत बना सकते हैं, आप ब्रिज बना सकते हैं, आप बिल्डिंग बना सकते हैं, परन्तु अगर आप समाज को एक साथ नहीं रख सकते, this Budget will remain just a piece of paper that cannot be implemented. Sir, I can go on and on and on. I want to say one more thing. Manipur is a small State, but Manipur is the gateway to East Asia. And, unless there is peace in Manipur, the entire North East area will remain disturbed.

In the NHM, they have given Rs. 514 crores, but I am sad to say that Manipur reported the highest average out-of-pocket expenditure in the country for institutional child-birth, which is one of the key priorities for NHM. I want to say that, due to the entire situation which unfolded, we have to have a debate on the Budget for the State of Manipur here but, I feel, that it is a case of missed opportunity that we could not give Manipur a message that we are with them.

सर, हम प्रधान मंत्री जी के विपक्ष में बोलते हैं। यह डेमोक्रेसी में होता है, परन्तु मेरा मानना है कि पूरे सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, चाहे वे मणिपुर के महाराज हों या मैं जो उत्तर-पूर्वांचल की एकमात्र सांसद हूँ, अपोजिशन में बैठी हूं, मुझे लगता है कि कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि मणिपुर में जो हुआ, that is unprecedented. ...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं है कि मणिपुर में President's Rule पहले नहीं हुआ है, वह जरूर हुआ है और मेरा विश्वास है कि बीजेपी के लोग बोलेंगे कि वह यहां हुआ, वहां हुआ, इस वक्त हुआ, उस हालात में हुआ, परन्तु मैं यह कहती हूं कि जिस हालात में मणिपुर में President's Rule हुआ, उसे यह देश कभी नहीं भूलेगा। इस बात को यह देश कभी नहीं भूलेगा।

सर, मैं इसकी chronology समझा देती हूं। वहाँ पर पहले 3 मई को हिंसा हुई। मेरी कॉम, जो हमारे यहां सदस्या थीं, उन्होंने 4 मई को Twitter में लिखा कि वहाँ थानों से weapons लूट लिये गये, गांवों के बाद गावों में आग लगा दी गई , परन्तु प्रधान मंत्री जी कुछ नहीं बोले। प्रधान मंत्री जी कुछ नहीं बोले। 29 मई को Peace Committee बनायी गयी। I admit that Amit Shah ji went to Manipur. I am not denying it. He made the Peace Committee, but the reason why that Peace Committee did not work properly is because they had objections to the hon. former Chief Minister of Manipur being a part of it. परन्तु बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया।

सर, 30 जुलाई को बीरेन सिंह जी ने resignation लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया गया, परन्तु दिल्ली से कोई नेता वहां नहीं गया। सर, पूरे 2024 में बीजेपी की MLAs यहां पर आते रहे, वे कहते रहे कि वहाँ लीडरशिप में परिवर्तन लाइए, परन्तु बीजेपी ने कोई भी कदम नहीं उठाया। ...(**व्यवधान**)... ऐसी क्या बात है? फरवरी में ऐसा क्या हुआ कि सीएम बीरेन सिंह को हटाया गया। वे खुद जाकर resignation दे आए। Sir, chronology is the key, the answer, to this question. आप देखिए, जुलाई, 2024 में गवर्नर को हटाया गया और मिस्टर भल्ला, जो इस वक्त गवर्नर हैं, उनको दिसम्बर, 2024 में लाया गया। जिस स्टेट में President's Rule है and Governor exercises power, मतलब ऐसे हालात हैं कि इन 6 महीने असम के गवर्नर को मणिपुर का चार्ज देकर रखा गया। इतनी अस्थिर व्यवस्था थी! There was no full-time Governor for Manipur. सर, फरवरी में क्या हुआ? सर, फरवरी में दो चीजें हुईं - पहला, if I am not wrong, Dr. Singhvi is here, 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Manipur tapes को Central Forensic Science Laboratory में भेजा जाएगा और किसकी आवाज वहाँ पर है, जो कह रहा है कि हाँ, मैंने मणिपुर में दंगे कराए, उसका जवाब 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। The tide started turning. ...(*Interruptions*)...

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रमोद तिवारी) : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिए कृपया आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... आप जितना बोलेंगे, मैं उतना एक्स्ट्रा टाइम उनको दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

MS. SUSHMITA DEV: Last but not the least ...(*Interruptions*)... Manipur State has not had an Assembly Session since 12th August, 2024. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रमोद तिवारी) : कृपया आप बैठ जाएँ, अन्यथा I will name you. कृपया आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

MS. SUSHMITA DEV: Sir, since August 12th August, 2024, Manipur State has had no Assembly. What does the Constitution say? Article 174 of the Constitution is very clear. You cannot have a gap of more than six months between two Assembly Sessions as per Article 174. What was the deadline? It was 12th February, 2025. अगर 12 फरवरी को असैंबली बैठती, तो क्या होता? यही होता कि मणिपुर के मुख्य मंत्री 'No Confidence' में हार जाते। This is the chronology, Sir. इसीलिए 9 फरवरी को सीएम बीरेन सिंह जी का इस्तीफा लिया गया। दो दिन वहाँ बीजेपी बैठी, कोई consensus नहीं बना। वह वहाँ सीएम के resignation के बाद सरकार नहीं बिठा पाई और 13 फरवरी को President's Rule लागू हुआ। Sir, the President's Rule was not imposed to save Manipur. जब 22 महीने मणिपुर जल रहा था, तब ऐसा नहीं हुआ। President's Rule was imposed to save the Bhartiya Janta Party and the Prime Minister from embarrassing political situation. And I tell you, Sir, that this has been exposed before the State. What do I expect from the hon. Finance Minister? My non-partisan view is, Madam, give Manipur a package. With folded hands, I am telling you, send them the right message, and, I am sure, that people of Manipur will unite again. माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ। मणिपुर के लोगों को बदनाम मत कीजिए। Manipur has fought insurgency for decades and come out of it. आपको डबल इंजन की सरकार का मौका दिया गया था, लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतर पाए। मणिपुर के लोगों को फिर से unite कीजिए और उसमें प्रगति हो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRAMOD TIWARI): Thank you. Now, Shri R. Girirajan. Do you want to speak in Tamil?

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRAMOD TIWARI): Okay. Go ahead.

SHRI R. GIRIRAJAN: Thank you, Sir, for giving me the opportunity. The Government is estimated to spend Rs.50,65,345 crores in 2025-26. This is an increase of 7.4 per cent over the Revised Estimates of 2024-25. The revenue expenditure is estimated to increase by 6.7 per cent and the capital expenditure is estimated to increase by 10.1

per cent over the Revised Estimates of 2024-25. Sir, a progressive State like Tamil Nadu is penalized for keeping the democratic rights of the people of Tamil Nadu as the top priority whereas some of the bigger States with very high population are getting the lion's share from the central exchequer. Sir, 60 per cent of total revenue

5.00 P.M.

generated is collected from Maharashtra and South Indian States like Tamil Nadu. But whether we are getting our due share of money back for our own development projects is a billion dollar question. The people of Tamil Nadu have been [£] by the Union Government year after year since 2014. This is undemocratic and untenable.

The Government proudly says that it has cut the fiscal deficit considerably. But behind this cut, we, the people of India, have to bear the heavy reduction in the allocation for the important schemes like MGNREGA. This is like cutting one's leg to fit the shoes. What else can we say? The hon. Finance Minister has [*] the aspirations of the people of Tamil Nadu being a Tamil mother by shrinking the share of funds allocated under various schemes to Tamil Nadu though the contribution of Tamil Nadu to the Central Exchequer is substantial. Our funds have been cut for SSA Fund and Flood Relief Fund.

Tamil Nadu is the most progressive State in the country with just four per cent of the total area of the country and just six per cent of the total population but contributes nine per cent of the total GDP to the country. Yet it received just 25 per cent from the Union Government for the implementation of projects in Tamil Nadu.

I would like to know from the hon. Minister what the contribution of some bigger States is where there is a *Double Engine ki Sarkar* to the country's GDP. Zero. And how much more funds are provided by the Union Government for these *Double Engine ki Sarkar* States whose population and extent are much higher than that of Tamil Nadu? I hope the Finance Minister has answer to this logical question.

I would like our Union Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, to take a leaf out of our hon. Finance Minister of Tamil Nadu to present a progressive, people-oriented Budget without compromising and without neglecting the interests of the poor, the downtrodden and the middle-class people.

[£] Expunged as ordered by the Chair.

[*] Not recorded.

The Government of Tamil Nadu has projected its revenue receipts at Rs.3,31,569 crore. The State's own revenue constitutes 75.3 per cent of total revenue receipts. The balance 24.7 per cent comes from the share in Central taxes and grants-in-aid from the Union Government. The Government's revenue from its own taxes are estimated to increase by 14.6 per cent in 2025-26. The expenditure of the Government of Tamil Nadu is projected to be Rs.4,39,293 crore in 2025-26 which is an increase of 9.95 per cent over 2024-25 Revised Estimates. The major portion is spent on various welfare schemes for the people, especially the poor, the vulnerable and the marginalised people.

The Government of India keeps on providing impetus to economic growth through spending for capital expenditure which is projected at Rs.57,231 crore which is an increase of 22.4 per cent over 2024-25 Revised Estimates whereas the Government of India has reduced the capital expenditure in order to reduce the fiscal deficit.

The Union Government's decision on reducing the allocation of MGNREGS and not to cut GST and taxes on petrol and diesel is a gross injustice to the people of India. Between 2014 and 2024, in the ten-year period, food inflation was 6.18 per cent, education inflation was 11 per cent and healthcare inflation was 14 per cent. These have crippled Indian households. Household savings have fallen from 25 per cent to 15 per cent. Average monthly per capita expenditure of a rural family is only Rs.4,226. In urban areas, it is Rs.6,996. It is not possible for the Government of India to achieve the goal.

The per capita income in Tamil Nadu is five times more than that of the per capita income of Bihar, three times more than the per capita income of Uttar Pradesh and almost twice that of the nation if Tamil Nadu's and Maharashtra's income are not included. This is the sorry state of affairs of the country. But the people in the Treasury Benches are challenging the people of Tamil Nadu by not providing their due share of funds for education, Railways, infrastructure, etc.

Sir, we have to pity on the people of Manipur. No State in India has seen more violence and murders than Manipur. The most pitiable part is that our hon. Prime Minister has travelled the length and breadth of the globe in the last three years, but is not having mind or compassion or humility to visit Manipur. Why? What prevents him? Who is stopping him? Why can't he visit the battered people of Manipur and have a few comfortable words with them? A few empty words were spoken by the hon. Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the Union Government to safely handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of

the shameful incident of public humiliation of two tribal women that led to the judicial intervention by the Supreme Court.

Now, after heavy £ and beatings, no matter how much money is provided to Manipur, the wounds in the minds of the people will never heal. ...(*Time-bell rings.*)... The scar will be there forever that stand as a testimony to the inadequacy of the Union Government. £ The people who murder democracy and federal rights of the people cannot bring peace and prosperity to any nation. History will teach them a big lesson very, very soon. Thank you.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : मान्यवर, आपने इस विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मान्यवर, मणिपुर के मुद्दे पर जब मैंने सदन में यह विषय उठाया था, हो सकता है कि मेरे तरीके से सरकार असहमत रही हो, लेकिन मुझे भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे लम्बे समय तक निलंबित रखा गया। मणिपुर का मुद्दा उठाने के कारण मैं 11 महीने तक निलंबित रहा। मान्यवर, मैं 11 महीने सदन से बाहर रहा।

मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक है। बीते पाँच महीनों में शेयर बाजार में देश के आम लोगों के 94 लाख करोड़ रुपये डूब गए। मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है, जब बेरोज़गारी पिछले 50 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी है। मणिपुर बजट तब आ रहा है, जब मोदी सरकार के इस कार्यकाल में भारत पर 186 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।

मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है, जितनी 100 साल पहले थी। महोदय, 'म' अक्षर से इनको बहुत प्रेम है – इनको 'म' से मटन याद रहता है, 'म' से मछली याद रहती है, 'म' से मुगल याद रहता है, 'म' से मुसलमान याद रहता है, लेकिन 'म' से मोदी याद नहीं रहता , 'म' से मणिपुर याद नहीं रहता!

मान्यवर, दो साल हो गए, मणिपुर जल रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए। इसके बावजूद, भारत के प्रधान मंत्री को दो वर्षों में एक दिन का भी समय नहीं मिला कि वे मणिपुर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें, वहाँ के लोगों के साथ खड़े हो सकें।

देश का प्रधान मंत्री देश का अभिभावक होता है, वह राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। सरकार लोगों की संरक्षक होती है, £ ऐसे में मणिपुर कैसे बचेगा? मैं यह बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेगा, यह देश गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, यह देश अहिंसा के आदर्शों पर चलेगा। मुझे अफसोस है कि पूरे देश में हिंसा क्यों हो रही है, आज पूरे देश में दंगे-फसाद की नौबत क्यों आती है, आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है, उसकी वजह यह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हैं,

---

£ Expunged as ordered by the Chair.

इसीलिए देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के 80 मुल्कों में साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं, लेकिन इसी संसद के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति मुख्य स्थान पर लगी थी, उसको आपने कोने में कर दिया, क्योंकि आपको गोडसे की पूजा करनी है, आपको देश में हिंसा फैलानी है, आपको नफरत फैलाने का काम करना है।

सर, टीएमसी की सांसद जिस ऑडियो की चर्चा कर रही थीं, शायद वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाईं- वह बहुत गंभीर ऑडियो है, उसकी जांच होनी चाहिए [¥] मान्यवर, उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। आप budget की बात कर रहे हैं। मणिपुर के लिए आपने क्या किया? सर, राज्य सरकार को, केन्द्र सरकार को जो ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**) : माननीय सदस्य, आपने जो कुछ भी कहा है, उसे authenticate करिएगा।

श्री संजय सिंह : यह audio सार्वजनिक है, इसको दिखा देंगे। सर, ऐसा राज्य, जो आज बदहाली में है, जहां पर 300 लोगों की जान जा चुकी है। वहां 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। उस राज्य में, जहां पर लोगों के 5,000 घर जलाए गए। उस राज्य में जहां पर 386 धार्मिक स्थान - जिसमें मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है और तमाम धार्मिक स्थानों को जलाने का काम किया गया। आज उस राज्य को मदद देने की बात आती है, जहां 18,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, 24,000 घर बाढ़ में बुरी तरह से तहस-नहस हो गए। 1.88 lakh लोग बाढ़ की चपेट में आए, तो ऐसे राज्य को जब मदद देने की बात आती है, तब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने बजट में जो बढ़ोतरी की है, 2024-25 में 34,899 crore का बजट था। आपने उस budget को revised करके 32,656 crore रुपये कर दिया। फिर उसी बजट को जब आप 2025-26 में लेकर आ रहे हैं, तो मात्र 5.5 प्रतिशत बढ़ाया और आपने उसको 35,103 crore रुपये का बजट कर दिया। मणिपुर के प्रति आपकी यह धारणा है, आपकी योजना है। केन्द्र सरकार के द्वारा जो scheme चलाई जाती है, उसमें आपने मणिपुर के साथ कितना भेदभाव किया है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा। प्रधान मंत्री आवास योजना में 72 per cent पैसे की कटौती की गई। आयुष्मान भारत योजना में 78 per cent पैसे की कटौती की गई, OBC Scholarship में 58 per cent पैसे की कटौती की गई, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में आपने 42 per cent पैसे की कटौती की और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 60 per cent पैसे की कटौती की गई। आपने 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' में 20 प्रतिशत की कटौती की, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान' में, उस राज्य के अंदर, जहां पर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुईं, बलात्कार की घटनाएं हुईं, उस राज्य के अंदर जहां एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस राज्य में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नाम पर आपने बजट में 49 प्रतिशत की कटौती करने का काम किया, आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स के बजट में 93 प्रतिशत कटौती करने का काम किया, आपने शेल्टर्स, जो वहां पर लोगों के लिए बनाने थे, उसके बजट में 73 प्रतिशत

[¥] Not recorded as directed by the Chair.

की कटौती की, आपने 'शक्ति सदन सामर्थ्य योजना' के बजट में 60 प्रतिशत की कटौती की, आपने 'साक्षी निवास सामर्थ्य योजना' के बजट में 81 प्रतिशत की कटौती की।

महोदय, यह आपकी सेंट्रल स्कीम है, जिसमें आपने राज्य सरकार के साथ भेदभाव किया और वहां पर कटौती करने का काम किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मणिपुर को 2 साल तक जलाया, आप देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं, आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं, देश की बेरोजगारी पर नहीं, किसानों पर नहीं, महंगाई पर नहीं है, आप दिन-रात औरंगजेब-औरंगजेब-औरंगजेब कहते हैं और जनता कह रही है कट गई जेब-कट गई जेब-कट गई जेब। यहाँ लोगों की जेब कट रही है, लेकिन आप औरंगजेब-औरंगजेब-औरंगजेब चिल्ला रहे हैं। आप हिंदुस्तान की चिंता कीजिए, ...(**व्यवधान**)... आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता कीजिए, गोडसे के रास्ते पर मत चलिए। गोडसे के रास्ते से यह देश आगे नहीं बढ़ेगा, यह देश गांधी के आदर्शों पर चलने से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको तो गांधी की मूर्ति से भी परहेज है, आपने उसको भी हटाने का काम किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज मणिपुर में जो 60 हज़ार लोग बेघर हुए हैं, क्या इस बजट में आपके पास उनके लिए घर बनाने की कोई योजना नहीं होनी चाहिए? आज मणिपुर के अंदर लोगों के जो घर जलाए गए हैं, क्या उनका घर बनाने की योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? आपने उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है, आपने मणिपुर के लोगों के लिए कोई चिंता नहीं की है।

महोदय, अगर, दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को उनके बीच सामंजस्य पैदा हो, उनके बीच एकता भाईचारा पैदा हो, इसके लिए उस राज्य में शांति की स्थापना के लिए काम करना था, लेकिन आपने वह काम नहीं किया। महोदय, 2 साल तक सारा विपक्ष चिल्लाता रहा - मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। आप राष्ट्रपति शासन तब लगा रहे हैं, [¥] इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए। आप मणिपुर की चिंता कीजिए कि मणिपुर में कैसे लोकतंत्र की बहाली हो। आप इस बात की चिंता कीजिए। महोदय, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है।

मान्यवर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर के बजट पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। मणिपुर के बजट की मणिपुर की विधानसभा में चर्चा होती, मणिपुर की योजनाओं के बजट के बारे में मणिपुर की विधानसभा में चर्चा की जाती, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर के बजट पर देश की संसद में, हम सब लोगों को चर्चा करनी पड़ रही है। वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहल कीजिए, वहां शांति की बहाली के लिए पहल कीजिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र खत्म होता है, अगर लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, तो तानाशाही आती है और तानाशाही किसी भी दृष्टि से, किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। अगर तानाशाही आती है, तो वहां दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, नफरत होती है। अगर दो समुदायों के बीच में झगड़ा होता है, तो लोकतंत्र की बहाली मणिपुर में कैसे होगी?

[¥] Not recorded as directed by the Chair.

महोदय, मणिपुर को आपकी तरफ से अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग कैसे दिया जा सकता है - इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। महोदय, प्रधानमंत्री जी फिर 'म' से मॉरिसस में हैं, लेकिन 'म' से मणिपुर कब जाएंगे - इस बात का इंतजार देश की जनता को है। आपको मणिपुर जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। आप अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, आप पूरी दुनिया भर में घूम लेते हैं, आप कतर हो आते हैं, आप दुबई हो आते हैं, कतर के शेखों को गले भी लगाते हैं। जैसे कुम्भ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, इस तरह से आप कतर के शेखों को गले लगाते हैं। ऐसे ही गले आप मणिपुर के भाइयों को भी लगाइए, मणिपुर के लोगों को भी लगाइए और उनको भी अपना सहारा दीजिए। आप देश के प्रधान मंत्री हैं, देश के अभिभावक हैं।

अंत में मैं फिर से आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि मणिपुर की चिंता करिए और देश में माहौल खराब करने के काम को बंद कर दो। नफरत फैलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRAMOD TIWARI): Now Shri Golla Baburao.

कोयला मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रमोद तिवारी) : एक मिनट, गोला बाबूराव जी। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Sir, kindly give me some more time.

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, सांसद महोदय ने बात करते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्रोसिडिंग के संबंध में गृहमंत्री के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ...(**व्यवधान**)... आपने नाम लिया है। गृहमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे अनुरोध करता हूं यदि उनके पास इसका कोई आधार है, तो वे जरूर सभा के समक्ष रख सकते हैं। नहीं तो, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसे रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। मैं माफी मांगने की डिमांड करता हूं। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसी गलत बात करना, संसद के सामने लोगों को गुमराह करने का प्रयास करना बिल्कुल गलत है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वह जो भी रिकॉर्ड है, उसे सबके सामने रखिए, नहीं तो मैं इस देश की जनता के सामने माफी मांगने की डिमांड करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैंने कहा है कि एक न्यूज वेबसाइट पर मुख्य मंत्री का एक ऑडियो पड़ा है। वह सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है और उसमें कही गई जो वार्ता है, मैंने उसका जिक्र किया है और मैंने उसकी जांच की मांग की है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, वह ऑडियो सही है या गलत है, उसकी जांच कराई जाए और यदि वह ऑडियो सही है, तो यह बहुत गंभीर है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने किसी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगाया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री प्रमोद तिवारी**) : कृपया, आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** कृपया, आप बैठ जाएं। यह अच्छा नहीं लगता। **...(व्यवधान)...** मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। **...(व्यवधान)...** माननीय मंत्री जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। **...(व्यवधान)...** संजय सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको जो कहना था, वह आप कह चुके हैं। माननीय मंत्री जी, आप अगर संदर्भ लें, तो मैंने यहां से निर्देश दिया है कि ऑथेंटिकेट करें और यदि नहीं करेंगे, तो नियम स्पष्ट है, उसके अनुसार कार्यवाही होगी। इसलिए मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, क्योंकि यह निर्देश जा चुका है और आपने पुनः कहा है, तो मैं वही निर्देश पुनः दोहराता हूं। Shri Golla Baburao, you can continue. आपका समय अब start होगा।

SHRI GOLLA BABURAO: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a great opportunity for me to speak on the Appropriation Bill today. In fact, Appropriation Bill means division of funds accrued from different sources to the Central Government which will be divided into States and the Centre and the Government will be empowered to draw it any time from the Consolidated Fund of India. As far as my knowledge is concerned, the Appropriation Bill is very, very important to allocate the funds as per the priority of the Government. Now, as seen from the allocations of different Departments, I straightaway want to tell the Finance Minister that it is really unfortunate to allot only two per cent of total funds to 80 per cent of the population in India. The allocation to Social Justice Ministry includes Scheduled Caste welfare, OBC welfare, minority welfare, women welfare, disabled welfare and senior citizens' welfare.

I want this august House to see the allocations made to these sections. As far as my knowledge goes, earlier, the Scheduled Castes Finance Development Corporation, the Backward Class Development Finance Corporation, and the Women Finance Development Corporation would receive huge funds and spend them on concerned departments. Unfortunately, the Government is doing injustice to the poorer sections in recent budgetary allocations. I would say that the Government may rename the Social Justice Ministry as Social Injustice Ministry. I request the Government to reconsider the Social Justice Ministry's allocations. I personally request the hon. Finance Minister, who has varied experience in Government departments, to rethink the allocations. She has been doing justice to all other departments, but is doing injustice to the Ministry of Social Justice and Empowerment. I also appeal to the hon. Prime Minister to rethink the allocations to these sections of society in the coming Supplementary Demands. I don't want to touch upon all the figures. I would only like to focus on the injustice meted out to the State of Andhra Pradesh. Unfortunately, in 2014, my State was forcibly reorganized by Parliament, which decided to divide the erstwhile State of Andhra Pradesh into two States — Andhra Pradesh and Telangana. They divided the State, but have not even

seen the face of Andhra Pradesh for the last twelve years. In the foothills of Lord Venkateswara, the hon. Prime Minister had promised to give Special Category Status to Andhra Pradesh. But, despite promises, no Special Category Status has been given. There is no respect shown to the State of Andhra Pradesh. It is being neglected in many sectors. The Central Government is in power with the support of the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu. If Shri Chandrababu Naidu's support were not there, the BJP Government at the Centre would also not be there. Please rethink about this. The people of Andhra Pradesh are watching everything and seeing the plight of Andhra Pradesh that it is being neglected in almost all sectors. What I want is to do justice to Andhra Pradesh now.

Though there are many demands, I would like to emphasize the Polavaram Project. It is a National Project. The Government of India must reconsider the Polavaram Project, regardless of the cost. I do not know what happened between 2014 and 2019. Only God knows! The Central Government has abdicated its responsibility for the Polavaram Project and handed it over to the State Government. I do not want to criticize anybody. I only want justice for the Polavaram Project. I am unclear about the funds allotted to the project.

In 2025, they have allocated only Rs.6,000/- crores. But, it requires nearly Rs.40,000/- crores. How can they complete the Polavaram Project now? Who will be responsible? If the Polavaram Project is not completed, entire storage of water, irrigation facilities or the entire development of the region will come to a standstill. I do not know who proposed this; they want to reduce the height of the Project from 45 metres to 41 metres. If they reduce the height from 45 metres to 41 metres, the people of Andhra Pradesh will not keep quiet. They will, definitely, raise a hue and cry; we will seek the support not only in Andhra Pradesh, but also of entire India. Sir, this Polavaram Project is the bone of contention between the Centre and the State.

Coming to steel plant issue, we all have now represented to the hon. Prime Minister and the Minister of Steel. But, only to remove the tears of Andhra people, they have granted only Rs.11,440/- crores. But, they have also not been released so far. Now, the VRS is being taken by the employees and the people are really scared. They do not know what will happen to the steel plant. I request the Union Government and the hon. Prime Minister to see that steel plant is protected and respect the sentiments of the Andhra Pradesh people. ...*(Interruptions)*... This is nothing but Appropriation Bill only. Nobody can deny it. These are all State issues and these are all only Central shares. Coming to railway zone for Vizag, I am very happy that the hon. Prime Minister has laid the foundation for the new Railway Zone in Visakhapatnam but they have not started any work so far. The Paralakhemundi of the

Waltair Division is not included in the new Railway Zone at Visakhapatnam. These things will be really reckoned with. People are not just blindly seeing all these developments; they will watch and say. What I want to say is that the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu and the JanaSena Adhipati, Shri Pawan Kalyan, both are very, very important to run the Government at the Centre. What I request is ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please conclude.

SHRI GOLLA BABURAO: Sir, give me one minute. I want Chandrababu Naidu *garu* and JanaSena to pressurise the hon. Prime Minister, place all the demands before him and fulfill the needs of Andhra Pradesh. Otherwise, a time will come when people of Andhra Pradesh will teach all these people a lesson in the coming elections. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : श्रीमती सुलता देव।

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा) **:** वाइस चेयरमैन सर, थैंक यू। देर आए, दुरुस्त आए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार डिमांड की है कि यहाँ मणिपुर के ऊपर चर्चा हो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहां बस डिस्कशन की डिमांड की, बल्कि हम लोगों ने हाउस भी छोड़ा और वहां पर प्रोटेस्ट भी किया। दो साल होने को आये, 22 months complete हो गये, लेकिन मणिपुर के ऊपर यहाँ कोई डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा था। चलिए, जो भी हो, आज यहाँ उस पर कम से कम डिस्कशन तो हो रहा है। जिस Appropriation Bill पर डिस्कशन मणिपुर की असेम्बली में होना चाहिए था, मगर चूँकि वहाँ पर राष्ट्रपति जी का शासन लागू हुआ है, इसलिए आज हम लोग यहाँ उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सम्भवतः यह दुर्भाग्य की बात है। वे लोग मणिपुर पर डिस्कशन करने से भाग रहे थे। लेकिन आज पहली बार यहाँ पर मणिपुर के 'Appropriation Bill' पर डिस्कशन हो रहा है। इसके लिए मैं सदन को भी धन्यवाद दूँगी और यहाँ पर वित्त मंत्री जी भी बैठी थीं, मैं उनको भी धन्यवाद दूँगी। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप यह स्पष्ट कीजिए कि मणिपुर भारत में है या नहीं है? मैं यह इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर मणिपुर पर डिस्कशन भी नहीं हो पाया, कोई मणिपुर गए भी नहीं, मान्यवर प्रधान मंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए था, मगर वे भी नहीं गए और जो मणिपुर जाना चाहते थे, उनको भी वहाँ जाने से रोका गया। मणिपुर से इतना डर क्यों है? मणिपुर के संबंध में ऐसा क्यों किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि मणिपुर हमारे देश से बाहर है? मेरी जानकारी जहाँ तक है, उसके अनुसार मणिपुर बहुत sensitive स्टेट है। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यह साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज़ से जमीन मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मणिपुर म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से अपनी मुक्ति सेना को लेकर

मणिपुर के रास्ते भारत आए और उन्होंने वहीं यानी मणिपुर में भारत का पहला झंडा गाड़ा था तथा वह आज भी वहाँ पर है। इसको हम deny नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है, तो फिर हम मणिपुर से क्यों भाग रहे हैं? किसलिए भाग रहे हैं?...(**व्यवधान**)... आप मुझे बोलने दीजिए। आप बार-बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सबको बोलने दीजिए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया आप बोलिए। आप इधर देख कर बोलिए।

श्रीमती सुलता देव : आज वहाँ पर मैतेई और कुकी संप्रदाय के बीच यह हो रहा है। पिछले दिनों वहाँ पर मैतेई और कुकी संप्रदाय के ऊपर इतनी हिंसा हुई कि इसके कारण मणिपुर जल रहा था। दो साल होने को आये, मणिपुर जल रहा था, लेकिन मणिपुर के बारे में कोई आलोचना नहीं हुई। मगर जब मणिपुर जल रहा था, तब हम लोग यहाँ पर सो रहे थे। मैं यही बात बोलूँगी कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे और जब मणिपुर जल रहा है, तो यह जो डबल इंजन की सरकार है, वह चादर तान कर सोई हुई है। उनके पास बाहर घूमने के लिए टाइम है, विदेश जाने के लिए टाइम है, मगर मणिपुर जाने के लिए टाइम ही नहीं है। मणिपुर जाने की मानसिकता भी नहीं है। हम लोग 'वसुधैव कुटुम्बकम' में विश्वास करते हैं। यह भारत की संस्कृति है। कहाँ गया 'वसुधैव कुटुम्बकम'? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? अगर वह भारत में है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? आज वहां पर आग क्यों लगी हुई है? वहाँ पर इतनी जानें क्यों गईं? मेरे पास जो डेटा है, मैं वह डेटा देती हूँ। "Loss of lives: At least, 258 people have lost their lives, including innocent civilians and militants – The Print." "Displacement: Over 60,000 individuals have been forced out of their homes leading to severe humanitarian crisis -- AP News." "Security lapses: Nearly 3,000 weapons were looted from police armouries, indicating a severe law and order failure -- Telegraph India." आप लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, मगर मणिपुर के बजट की आलोचना हो रही है। जब मणिपुर के बजट की आलोचना हो रही है, तो आपको यह देखना चाहिए कि मणिपुर के बजट में सामाजिक विकास के लिए ज्यादा आवंटन होना चाहिए, वहाँ की महिलाओं के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, बच्चों के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। वहाँ पर जो लोग घर से बेघर हुए, जिनको विस्थापित किया गया, उनके लिए पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, मगर इन सबके लिए पता नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्यादा पैसा है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? इसमें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास के बजाय लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्यादा पैसा दिया गया है। आप इससे वहाँ क्या करेंगे? आप तो ऐसे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपके गवर्नर खुद बोले कि इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। यहां आइए, आलोचना कीजिए। आपने तो उनकी बात भी नहीं सुनी। फिर आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? फिर भी मैं बोलूंगी कि "Double engine run over the people of Manipur." हमने डबल इंजन सरकार के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। डबल इंजन की सरकार इतनी स्पीड से गई और क्या हुआ, उसके बारे में हम सबको मालूम है। आज ओडिशा में वैसे ही डबल इंजन सरकार की बात चल रही है। मगर, डबल इंजन हो गया। वैसे ही, कल मणिपुर हो

रहा था और आगे ओडिशा की भी बारी आ सकती है। उसके बाद और कोई स्टेट, फिर और कोई स्टेट, इस तरह पूरे भारत की बारी आ सकती है। मैं यह इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि ओडिशा में पिछले 7 महीनों में 64 मास रेप केसेज़ दर्ज हुए हैं। जब वहां होली खेली जा रही थी, तो एक ही दिन में वहां सात आदमियों के मर्डर्स हुए, जबकि हमने देखा कि £ वहां 5-5 साल की दो लड़कियां, जिनमें से एक की थी और दूसरी Jaipur की थी, उन दोनों को मास रेप करके मार दिया गया। जैसे, मणिपुर जल रहा है, वह भी वैसे ही जलेगा। मणिपुर से महिलाओं की जो नग्न और वीभत्स तस्वीरें आई थीं, वह एक शर्मनाक बात थी। मुझे नहीं पता, मगर इसने कहीं न कहीं हमारे भारत पर एक धब्बा लगा दिया है। मैं आज भी यह बोलूंगी कि मणिपुर के बारे में सरकार को केवल सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को कदम भी उठाने चाहिए। मणिपुर में न्यूट्रिशनल बजट को 25% कम कर दिया गया है। वहां ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग बजट है, उसको 47% कम कर दिया गया है। मणिपुर में डिमांड फॉर ग्रांट्स को ज्यादा किया जाना चाहिए। यह मणिपुर की ही बात चल रही है। वहां 6 महीने से लेकर 6 साल तक के 6,164 चिल्ड्रन, 2,638 adolescent girls, 232 pregnant women और 752 lactating mothers 325 camps में रह रही हैं। वहां अप्रैल, 2024 तक 554 बच्चे रिलीफ कैम्प्स में पैदा हुए हैं। उनमें दो maternal deaths भी हुई हैं, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 2022 के बाद प्रधान मंत्री जी ने मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन वे 40 बार फॉरेन टूर कर चुके हैं। क्या मणिपुर हमारी कंट्री में नहीं है? क्या वे मणिपुर नहीं जा सकते हैं? मैं माननीय गृह मंत्री जी को साधुवाद देती हूं कि वे 29 मई, 2023 को मणिपुर गए। उन्होंने मणिपुर में जाकर एक Peace Committee बनाई, लेकिन उसको बनाने का कुछ फायदा नहीं हुआ। वहां के जो गवर्नर थे, उनको जबरदस्ती हटाया गया और उस पीस कमेटी का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि वे चाहते थे कि लोगों की आलोचना हो, प्रधान मंत्री आएँ। मैं अभी भी बोलूंगी कि मणिपुर हमारे भारत में है, आप वहां जाइए और लोगों से मिलिए। मैं डिमांड करूंगी कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अर्थ की व्यवस्था हो, क्योंकि ज्यादा देने से कम से कम उनके जो जख्म हैं, उन पर मरहम लग सकता है।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह भी दरख्वास्त करूंगी कि आप मणिपुर जाइए और वहां लोगों के जो जख्म हैं, उन पर मरहम लगाइए। वहां लोग आपको देखें और आप लोगों की सुनें। वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी जाकर वहां के लोगों के जो हरे जख्म हैं, वे भरेंगे, मगर अभी यह सब नहीं हो रहा है। अभी मणिपुर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। क्यों ? क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, वहां पर £ की गई है। हम बोलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड में सबसे बड़े गणतंत्र हैं, मगर मणिपुर में £ की गई है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन कहीं लागू नहीं होता है, वह लागू होता है, मगर जिस सिचुएशन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उसकी जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, वह कम है। आप इसको जरूर देखिएगा, यह इतिहास में भी काले

£ Expunged as ordered by the Chair.

अक्षरों में लिखा रहेगा। मैं फिर से बोलूंगी कि आज इस चर्चा के माध्यम से हमने जो कहा है...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सुलता देव : सर, मैं बस कनक्लूड कर रही हूं। मणिपुर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजट ज्यादा देना चाहिए, महिला और शिशु के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। Thank you so much.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : श्री मनोज कुमार झा, seven minutes.

श्री मनोज कुमार झा (बिहार) **:** सर, जब आप कहते हैं, इतने मिनट्स, तो मुझे लगता है कि फांसी से पहले पूछा जा रहा है कि बता तेरी रज़ा क्या है? सर, दो तीन छोटी-छोटी चीजें हैं, उसी को कहूंगा। ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मणिपुर को यहां के संवाद से, यहां के विमर्श से यह लग रहा होगा कि वह हमारे देश का हिस्सा है। सर, एप्रोप्रिएशन का मामला है, मैं बजट के दौरान अक्सर एक बात कहता रहा हूं कि अपने देश में Directive Principles में आर्टिकल 39, सब-क्लॉज़ C है – आज हम सबको ज़रूरत है कि हमारा बजटीय प्रावधान उस लेंस से देखा जाए, ताकि आय का संकेंद्र न हो, आय का समान वितरण न हो और बाद में जब कोई राज्य सरकार Piketty को बुलाती है, तो उस पर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं, खैर यह अलग मसला है।
सर, मैं दो-तीन छोटी छोटी चीजें कहने से पूर्व सबसे पहले तो यह कहूं कि आज जो भी दो-चार चीजें कहूंगा, वे मणिपुर के अपने भाइयों-बहनों, उनके मृतकों और उनके विस्थापित लोगों को समर्पित है। आलोचना नहीं है, शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अपने संदर्भ में कुछ चीज़ों को रखूंगा।
सर, आपने सोशल डेवलपमेंट के ऊपर सिक्योरिटी को तरजीह दी है। मैं security phenomena को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप तह में जाएं, तो यह मई, 2023 में क्यों शुरू हुआ? एक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया, हम उसका अवलोकन नहीं कर पाए कि इस निर्णय का अंजाम क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था।

दूसरा, ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट को लेकर बहुत आशंकाएं हैं, उसमें भी एलोकेशन बहुत ही छोटा है, compared to other heads. सर, disaster-prone State है। हमारी सुलता जी कह रहीं थीं कि strategic importance का स्टेट है, लेकिन disaster-prone भी है, वहां आपने मात्र 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। It does not speak very good about us. Transparency and Accountability पर कई चीजें हैं, जिन पर मैं बाद में आऊंगा।
सर, एक क्वोट करना चाहता हूं। Janina Bauman जो थीं, वे Zygmunt Bauman की पार्टनर थीं, holocaust survivor थी। उन्होंने 'Winter in the Morning' में एक लाइन लिखी "The cruelest thing about cruelty is that it dehumanizes its victims before it destroys them. And that the hardest of struggles is to remain human in inhuman conditions." अगर इसका तर्जुमा अपने हिसाब से करूं, तो क्रूरता के साथ सबसे क्रूर चीज़ यह है कि यह अपने victim को खत्म करने के पूर्व उनके मानवीय मूल्यों को विलग कर देती है। अतः इस तरह के

माहौल में मानवीय संवेदना बचा कर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सर, हम मानवीय संवेदना को मणिपुर के बरअक्स बचा कर नहीं रख पाए। जैसे कहते हैं:

देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें,
मगर इस शहर में तुम्हें कातिल ढूंढ़े से नहीं मिलेगा।

मणिपुर में यही वाकया है। सर, मैं एक बात कई दफा पार्लियामेंट के बाहर कह चुका हूं, आज यहां दोहरा रहा हूं। चुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधान मंत्री होता है। देश का प्रधान मंत्री मेरा भी प्रधान मंत्री है, तो किससे शिकायत करूंगा, किससे उम्मीद रखूंगा और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर प्रधान मंत्री जी मणिपुर जाते, तो स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। प्रधान मंत्री का पद और कद दोनों बड़े होते हैं। आप मलहम लेकर जाते। आपकी मौजूदगी मलहम का काम करती है। न जाने क्यों नहीं गए? बचपन से पढ़ते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मध्य प्रदेश। सर, ये नफरत के बारूदी कारोबार ने इस देश को ऐसे बहुत संकेत दिए हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं, प्रीतिकर नहीं लगते हैं, unsettle करते हैं, परेशान करते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है और देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके उदाहरण हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह नहीं चल पाया, अगर उसके समुदाय के लोग, अलग-अलग समुदाय बारूदी नफरत के कारोबार में लगे रहे। हमें यह सीखना होगा।

सर, मणिपुर में संस्थाओं से लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ सा गया है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं संसदीय पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ मेम्बर्स के साथ गया था। हम सब वहां की गर्वनर साहिबा से मिले। उनके अंदर जो भाव था, जो पीड़ा थी, वह पीड़ा मैंने दिल्ली दरबार में नहीं देखी। दिल्ली दरबार में उस पीड़ा का शतांश भी होता, तो आज दो वर्ष तक मणिपुर को इस बहस के लिए, इस बातचीत के लिए इंतजार न करना पड़ता। शायद आज उन्हें लग रहा हो, एक संदेश गया हो कि वह भी इस देश का हिस्सा हैं। हमारी ओर से काफी delayed response रहा। एक peace panel बना। उसके निर्माण काल से ही वह controversial रहा। उसके composition को लेकर उसमें जो अलग-अलग सदस्य थे और उसमें लोगों की भावनाएं थीं, उसमें लोगों ने कहा कि इस पैनल को, और वह पैनल एक भी दिन काम नहीं कर पाया। सर, कल्पना कीजिए जलते हुए मणिपुर में, हिंसा ग्रस्त मणिपुर में एक peace panel बना और उस peace panel की एक भी मीटिंग न हो पाई हो। सर, अभी हाल में last date दो बार extend की गई कि लोग हथियार लौटा दें। मुझे जानकारी नहीं है कि कितने हथियार लौट कर आ गए और कितने नहीं आए। हमें लगता है कि संभवतः मंत्री जी अपने रेस्पॉन्स में बताएं, लेकिन हथियारों के लौटने से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं यह नहीं कहूंगा कि खाइयां आपके दल ने पैदा की हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में, लोगों के बीच में इतिहास की समझ को लेकर, वर्तमान की चुनौती को लेकर खाइयां रही हैं, लेकिन सुलह इस देश का default template था। Peace building was the default template. हमने उस default template को खारिज कर दिया है। क्षेत्रीय असंतुलन, जो सामुदायिक असंतुलन में तबदील होता है और वो सारी चीज़ें उस तरह के असंतुलन, समुदायों के बीच की दूरी

को और बढ़ा रहे हैं। मैं अंत में आपके माध्यम से सिर्फ यह आग्रह करूंगा कि देश में political parties की आयु सीमित होती है, सरकारों की आयु सीमित होती है। आज आपको एहसास हो रहा होगा कि आप अगली बार भी जीतेंगे, लेकिन उस अगले का कोई अगला होगा। उस अगले के अगले का कोई अगला होगा, वहां जीत की गाड़ी रुकती है, इनकी रुक गई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर देश में अलग-अलग हिस्सों में मणिपुर जैसे हालात रहेंगे, तो हम पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए बना रहे हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक आग्रह और होगा कि मणिपुर को लेकर अभी भी वक्त नहीं बीता है। अलग-अलग इलाकों में एक all-party delegation वहां जाए। चाहे कुकी समुदाय हो, मैतेई समुदाय हो, उन्हें वहीं रहना है, मिलकर रहना है। जैसे नॉर्थ-इंडिया में जिन समुदायों के बीच में नफरत की फसल बोई जा रही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, यहीं रहना है, अगर यहीं रहना है, तो शांति से रहना होगा, न्यायप्रियता के साथ रहना होगा। अगर हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम हार जाएंगे। हमारा हारना छोड़ दीजिए, देश हार जाएगा और जब देश हार जाएगा, तो हमारे हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको इस वक्त के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** मैंने आपको ज्यादा वक्त दिया।

श्री मनोज कुमार झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट ज्यादा वक्त दिया। मैं जय हिंद बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : आप बोलिए।

श्री मनोज कुमार झा : सर, तीस सेकेंड लेना चाहता हूं। सर, मणिपुर की इस चर्चा के लिए सारे सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमारी भूमिका यहीं खत्म नहीं होती है। मणिपुर को यह संदेश देना होगा you belong to us. We are nothing without you. जैसे एक-एक हिस्से के बगैर हमारा कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं है। यह मैं मणिपुर के सभी समुदाय के लोगों को समर्पित करता हूं। जय हिंद!

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** धन्यवाद, मनोज कुमार झा जी।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order, under calmer circumstances, just to set on record as to what was going wrong. Please allow me. The rules are very clear. Please, humbly look at Rules 258 and 259. The basic point here is today, all of us know we are discussing the Ministry of Railways. What happened today is that the Minister, at the end of his speech used the expression 'Railway Budget'. We were not discussing the Railway Budget. That practice stopped in 2016. What happened today has to be removed from the records. This is

the point we were trying to make. There were other points also. It is Rule 259. Please allow me to say this. It relates to Rule 258 also. It is the right of a Member, any Member, irrespective of the Party, this side or that side, and, it is the guaranteed right of a Member to raise a point of order. These are the two very serious issues which happened today. It needs to be corrected in the records, otherwise, it gives a bad impression. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी समय, आवश्यकता होने पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। जब आपने यह प्रश्न उठाया था, तो मैंने आपको एलाऊ कर दिया था और आपसे नियम बताने के लिए कहा था। जहाँ तक दूसरे प्रश्न की बात है, माननीय महोदय आज रेलवे के कामकाज पर ही चर्चा हुई थी, रेलवे के बजट पर चर्चा नहीं हुई थी। इस प्रकार से आपके व्यवस्था के प्रश्न का समाधान किया जाता है। Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. On behalf of my Party leader, Shri Edappadi Palaniswami, I rise to participate in the discussion on the Manipur Budget and the Appropriation Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : इसके लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, even though we are opposing the imposition of President's Rule, that is, Rule 356 in the State of Manipur, yet, we are supporting the passage of this Bill.

Mr. Vice-Chairman, Sir, just now, hon. Member from the DMK said that they could not get revenue share for Tamil Nadu. Sir, I have come across a news, and, I want to know whether it is a fact that ED has raided many liquor factories in Tamil Nadu? Is it a fact that loss worth thousands of crores of rupees has happened. Is it a fact? Does the Government know about it? What is the action they are going to take? Sir, they are demanding more revenue while the revenue is being misused by the Ruling Party, the State Government, the Stalin Government is misusing the funds, why are they blaming others? ...(*Interruptions*)...

श्री जयराम रमेश : यह सब्जेक्ट ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: No, let me speak. Is it not a fact that ED has raided? It is a matter of Rs. 1,000 crores. ...*(Interruptions)*... Let the Minister speak as to how this

kind of corruption took place in Tamil Nadu. Corruption is so prevalent in Tamil Nadu that the people are against the Government. Sir, many welfare programmes ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : एक मिनट, कृपया चुप हो जाइए। देखिए, मणिपुर के साथ-साथ Appropriation Bill भी हैं। उन पर भी चर्चा हो रही है, इसलिए माननीय सदस्य बोल सकते हैं। माननीय सदस्य, आप बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: This is what I am saying, Sir. It is relating to the Appropriation Bill. It is regarding the finance. Hon. Member compared Uttar Pradesh and Bihar. When they are saying that Tamil Nadu is better than Uttar Pradesh and Bihar, what about Maharashtra? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seat.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I have every right to speak here. Why am I telling this? ...*(Interruptions)*... They cannot compare an under-developed State and tell that Tamil Nadu could not get its due share. ...*(Interruptions)*... They have to compare Tamil Nadu with Maharashtra. ...*(Interruptions)*... Maharashtra's industry is developed. ...*(Interruptions)*... Tamil Nadu's industry is developed. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : एक मिनट। माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न है। He is on a point of order. Please sit down. आप बोलिए, कौन-सा रूल है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): No Rule; no point of order. Please continue, Dr. Thambidurai.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, the point of order is, how he can be allowed ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Wilson ji, please listen to me. Point of order पर point of order नहीं आता। आपके माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उनको बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए। Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, please listen to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please speak.

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, he is not talking about...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Under which rule?

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, it is under Rule 258. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): No Rule! No point of order. Please continue, Dr. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, a news regarding Tamil Nadu has come that the ED Director himself said clearly that it could be thousands of crores. ...*(Interruptions)*... Even the concerned Minister of the State said that it could be worth 40,000 crores of rupees.

6.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, कृपया एक बार बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, अभी वक्ताओं की सूची और भी है और आज का कार्य भी करना है। अगर सदन की सहमति हो, तो समय को बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आज के कार्यसूची के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। ...(**व्यवधान**)... वक्ताओं की जो आज की सूची है, वह आगे चलेगी और मंत्री जी कल जवाब देंगे। सदन की सहमति से समय को आगे बढ़ाया गया है। आप बोलें।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to reiterate it here because I am concerned about the Government of Tamil Nadu.

श्री जयराम रमेश : सर, भोजन की व्यवस्था ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : दोनों की व्यवस्था करेंगे। आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था करेंगे और भजन की भी व्यवस्था करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: We want sufficient funds. I am speaking only for that. That share has to come. When that kind of corruption is taking place in Tamil Nadu in sales and everything, the revenue on GST may not come for the Central Government. Then, how can they give? That is what I am trying to tell. Also, they are making comparisons. Tamil Nadu is one of the developed States. I am not denying that. This is not because of one person. This is because of our leaders Puratchi Thalaivar MGR, Madam Jayalalithaa and Edappadi Palaniswami. These are the tall leaders. They have brought so many welfare schemes. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. GIRIRAJAN: *

DR. M. THAMBIDURAI: All welfare schemes brought by the AIADMK Government have been closed by the DMK Government. ...(*Interruptions*)... That is the present position. What kind of welfare programmes are you going to implement?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : डा. मु. तंबी दुरै जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड नहीं होगी। आप बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Nowadays, we want to bring investment from various countries here. When the State Government is not promoting its own industries and going to other countries to attract investment, what is the purpose? You make development here. For example, under the education policy, they are approving more CBSE schools. Why are they approving more CBSE schools? They are giving no objection to CBSE schools. They are having matriculation schools. They can develop them. ...(*Interruptions*)... I won't appreciate going on criticizing one Government for hiding their mistakes. First, you have to see that there is discrimination in Tamil Nadu. Our colleague, Mr. Chidambaram, was Finance Minister for so many years. How much money did he allocate for Tamil Nadu? Why is Tamil Nadu not developed? It is because he also discriminated. They are in alliance with Congress. Let them say whether Mr. Chidambaram allocated more money for the development of Tamil Nadu. They ruled for so many years, but they have not done anything. They are having alliance with Congress and Congress imposed Article 356 many times and dissolved many elected Governments. ...(*Interruptions*)... I am coming to Manipur. ...(*Time-bell rings*)...

---

* Not recorded

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : कृपया समाप्त करें।

DR. M. THAMBIDURAI: Many elected Governments were dissolved by the Congress. Even DMK Government was also dissolved.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : प्लीज़, समाप्त करें।

DR. M. THAMBIDURAI: Our Government was also dissolved by the Congress Government. And they are having alliance with them. This is the pity.

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : प्लीज़, समाप्त करें।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, we have to develop Manipur. I am supporting giving them funds. At the same time, because they raised concern about Tamil Nadu, I am telling you that because of the corruption ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : कृपया समाप्त करें। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. Now, Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, there is an additional expenditure of Rs. 6.70 lakh crores. This amount is other than the provisions in the Budget Estimates. Both Supplementary Demands for Grants 1 and 2 stand as one-seventh of additional expenditure to the Budget. It reflects that the Ministry of Finance has significantly failed to foresee the Government expenditure. As far as the budgetary expenditure is concerned, under the head 'Relief and Disaster Management', there is a 25 per cent cut on the budgetary expenditure. What does this mean, Sir? This means that the immediate relief for displaced persons and affected communities has been de-prioritized by the Government.

That cannot be done. Disaster has been happening over there for last so many months. As far as budgetary provision for police is concerned, there is a cut of 4.7 per cent. Given the ethnic tension and security challenges which the State is facing over there, reducing the funds for policing is going to be catastrophic. I do not know why funds are being reduced as far as police is concerned and as far as relief and disaster management is concerned. As far as public works and infrastructure are concerned, there is a reduction of 32.3 per cent. We know that entire buildings have

been demolished over there. The houses have been destroyed over there. Business establishments have been destroyed over there. Given the destruction of homes, business ventures and roads due to violence, there should have been an increase in the Budget. Instead of an increase, there is a reduction of 32.3 per cent as far as the public works and infrastructure are concerned. As far as allocation for education and healthcare is concerned, there is not much allocation. There has to be a higher allocation for education and healthcare system. We have to rebuild schools as they have been destroyed over there. Funding for health has to be increased. Everybody over there has got some kind of illness or the other. Special Economic Package is not there. There has to be a Special Economic Package for the affected communities, traders and farmers. Nothing of that sort is there in the Budget. In the Budget, there is an earmarked fund of Rs.113 crore for rehabilitation. The Budget documents say that it is the priority of the Government. Is this allocation based on any assessment? We need to know if there is any assessment by the Government for this allocation. How many people died in the State due to this violence? How many people have been displaced from there? How many houses have been torched? How many churches have been torched? How many temples have been torched? All the data have to be there. Is there any assessment made by the Government before making this allocation? We do not know that. What is the total loss for the State economically? We do not know that. Is there any economic reason behind this violence? ...*(Time-bell rings)*... Has it anything to do with activities like timber trading?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

SHRI HARIS BEERAN: I am concluding, Sir. A more positive approach should have been there with higher allocation for all those things which are in dire straits. Priority has to be given for long-term livelihood issues. Support should be there to address the concern of the people of Manipur. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद। श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** सर, basically, पांच Finance बिल्स हैं, जिनमें तीन तो मणिपुर से संबंधित हैं और बाकी दो Union Government से संबंधित हैं। सर, पहले मैं शुरुआत मणिपुर से कर रहा हूं, क्योंकि मणिपुर के बारे में ही सबसे अधिक बातें आई हैं। जब ये मणिपुर की बात कर रहे थे, तो मणिपुर में किस प्रकार से अभी शांति-व्यवस्था चल रही है और कैसे वहां पर सुधार हो

रहा है, यह लोगों को पता होना चाहिए और उसके अनुरूप ही बात करनी चाहिए, नहीं तो फिर इस प्रकार से बात करने से वहां लोगों को भी तकलीफ होती है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

वहां दो समुदायों में, दो वर्गों में आपस में झगड़ा कराने का काम, आपस में बांटने का काम किसने किया? वह तो कांग्रेस की सरकार ने ही किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : सर, ये क्या बोल रहे हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam *ji*, please take your seat.

श्री अरुण सिंह : सर, यह कोई अभी का मामला नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह 40-45 साल पुराना है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him. अरुण सिंह जी, सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अरुण सिंह : सर, 1993 में जब मणिपुर में दंगे हुए, मणिपुर में 750 मौतें हुईं और 305 गांव तबाह हो गए, तब कांग्रेस की सरकार थी। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस के प्रधान मंत्री तो छोड़िए, कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री नहीं गए! यह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार है। ...(**व्यवधान**)... यहां के गृह मंत्री, अमित शाह जी तीन दिन जाकर मणिपुर में रहे और गृह राज्य मंत्री तीन महीने जाकर मणिपुर में उस समय रहे। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में difference है! ...(**व्यवधान**)... आप तो वहां गए ही नहीं! ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, सुनिए। अपनी सीट पर बैठे-बैठे न बोलें।

श्री अरुण सिंह : और तो और, जब मणिपुर उस समय, 1993 में जल रहा था, तो इस संसद के अंदर गृह मंत्री ने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब देने के लिए खड़ा किया, तो MoS को खड़ा किया। कभी राजेश पायलट, तो कभी किसी को, लेकिन उन्होंने खुद कभी जवाब नहीं दिया। आज वह कांग्रेस मणिपुर की बात कर रही है! ...(**व्यवधान**)... सर, अभी भी बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, अभी अगर मणिपुर की बात बताता हूं, तो मणिपुर में एक प्रकार से विकास तेज गति से चल रहा है और धीरे-धीरे सब शांति-व्यवस्था हो रही है। करीब 7 हजार लोग रिलीफ कैंप से घरों में आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहां 400 करोड़ रुपए रिलीफ पैकेज के लिए भी दिए हैं। अभी जो केंद्रीय बजट है, उसमें भी 500 करोड़ रुपये contingency fund के लिए दिया गया है। उसके अलावा अगर मणिपुर से संबंधित देखें, तो 1,861 करोड़ रुपए जो एडिशनल खर्च 2024-25 का है, उसके लिए भी अभी बिल लाए हैं, वह भी यहां पर अभी पेश हुआ है।

सर, अभी latest बात बता रहा हूं। पूरे देश भर में 6 दिसंबर, 2024 को 28 नवोदय विद्यालय, उनकी सैंक्शन हुई कि 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे, जिनमें से तीन जो विद्यालय होंगे, वे मणिपुर में होंगे। यह मोदी सरकार की अभी की अनाउंसमेंट है। 7 मार्च, 2024 को जो अनाउंसमेंट हुई, 10,037 करोड़ रुपए की industrial और employment generation के लिए बहुत बड़ी परियोजनाओं की अनाउंसमेंट हुई है। Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 में भी अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं जा रहा है, तो वह मणिपुर को जाएगा।

सर, यह मोदी सरकार ही है कि अगर देश में देखें, देश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बनी, तो मोदी सरकार ने मणिपुर में ही बनाया, ऐसा मणिपुर से लगाव है। आप सुनते जाइए। North-Eastern Special Infrastructure Development Scheme, जो 2017-18 में approve हुई, वह 2024-25 में अभी भी चल रही है। मैं जल्दी-जल्दी बताना चाहूंगा कि उसके अंदर अगर 8 रोड्स और ब्रिजेज़ के 375 करोड़ के projects कहीं approve हुए, तो मणिपुर के लिए हुए हैं। अगर 2,411 करोड़ के 235 projects, other than roads and infrastructure, approve हुए हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के लिए हुए हैं। इसके अलावा, मणिपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मणिपुर में आईटी के लिए SEZ, मणिपुर में 60-bedded State mental hospital, मणिपुर में infrastructure development के लिए यूनिवर्सिटी - ऐसे अनेकों काम मणिपुर के लिए हुए हैं। वास्तव में जब से मोदी सरकार है, मणिपुर के लिए, पूरे नॉर्थ-ईस्टर्न रीज़न के लिए दिल खोल फंड दे रही है।

सर, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी, तो उसने मणिपुर को 2004 से 2014 तक, 10 सालों में tax devolution के रूप में 7,696 करोड़ रुपए दिए। उसने मणिपुर के लिए 10 साल इतने रुपये दिए। यह मोदी सरकार है और इसने tax devolution के रूप में उसी मणिपुर को, जो हमारा मणिपुर है, उसको 46,312 करोड़ रुपए, मतलब पांच गुना अधिक फंड देने का काम किया है। यह मोदी सरकार ने दिया है। अगर grant-in-aid देखें, तो आपके समय में 10 सालों में 31,000 करोड़ रुपए दिये गए थे और हमारे समय में 76,000 करोड़ रुपए देने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। उसके अलावा, चूंकि आप मणिपुर के बारे में बहुत कह रहे थे, तो मणिपुर के बारे में ढंग से बातें सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: John Brittasji, please!

श्री अरुण सिंह : आप मणिपुर की ही बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairamji, please sit down.

श्री अरुण सिंह : मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के 1,026 किलोमीटर के 50 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स अगर कहीं सैंक्शन हुए, तो मणिपुर में हुए। ...(**व्यवधान**)... इसके अलावा, 9 मार्च 2024 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने अगर फाउंडेशन स्टोन का lay down किया है, उसका भूमि

पूजन किया है, तो 3,400 करोड़ रुपए के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स केवल और केवल – यह लेटेस्ट है। यह 9 मार्च, 2024 की बात है। आप अपनी आंखें कुछ खोल लीजिए, मणिपुर के लोगों से बात कर लीजिए। ...(**व्यवधान**)... मणिपुर के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार उनकी मदद कर रही है और उनके नजदीक है। वे डबल इंजन की बात कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No interruptions please!

श्री अरुण सिंह : सर, टीएमसी वालों ने भी डबल इंजन की बात कही। ...(**व्यवधान**)... जिनकी एक-एक राज्य में सरकार है, वे ऐसी बात करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है, जो प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में 21 राज्यों में सरकारें हैं। एक राज्य वाले क्या बात करेंगे? अभी टीएमसी वाले बात कर रहे थे। ये डबल इंजन की बात कर रहे थे। पहली बार हमने हरियाणा में ऐसी सरकार बनायी; पहली बार आसाम में हमारी डबल इंजन की सरकार बनी; पहली बार हमारी डबल इंजन की सरकार अरुणाचल में बनी और 27 साल बाद पहली बार डबल इंजन की हमारी सरकार अभी दिल्ली में बनी है। यह मान कर चलिए कि जब अगला चुनाव पश्चिम बंगाल का होगा, तो पहली बार TMC की भ्रष्ट ...(**व्यवधान**)... सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और वहां भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ...(**व्यवधान**)... जब बोला है, तो सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please! ...*(Interventions)*...

श्री अरुण सिंह : सर, पश्चिमी बंगाल में कोई कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has a point of order. ...*(Interventions)*... Tell me under which rule.

DR. JOHN BRITTAS: Enabling Rule is Rule 258 but I am quoting Rule 240.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you talking about Rule 258?

DR. JOHN BRITTAS: No, Sir. That is enabling. I am referring to Rule 240.
"The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used...". He is repeating again and again. ...*(Interventions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. No point of order, please. ...*(Interventions)*... Okay, thank you. Please take your seat. ...*(Interventions)*... Nothing is going on record. ...*(Interventions)*... कृपया आप बोलें।

श्री अरुण सिंह : सर, हम पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पर सरकार बना कर ही रहेंगे। वहाँ हमें कोई रोक नहीं सकता है।

सर, मणिपुर में 11 लाख लोगों का जन-धन अकाउंट खुला है। उसके साथ, मणिपुर में 'पीएम मुद्रा योजना' के अंतर्गत 2,850 करोड़ रुपए का disbursement हुआ है। 'स्टैंड-अप योजना' के अंतर्गत 57 करोड़ रुपए का disbursement हुआ है। उसी के साथ-साथ, 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के अंदर भी 438 applications सैंक्शन्ड हुए हैं, जिनमें 56 परसेंट महिलाएँ हैं।

सर, इनको सुनना चाहिए कि मणिपुर के लिए क्या किया गया। मोदी सरकार में 'पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना' के अंदर 3.5 लाख लोगों का enrolment हुआ है, 'अटल पेंशन योजना' के अंतर्गत 63,400 लोगों को लाभ मिला है। और तो और, शुद्ध पीने का पानी, जो कांग्रेस के समय नसीब नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार के 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से मणिपुर में 3 लाख, 30 हजार घरों में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। ये कह रहे थे कि लोगों के मकान नहीं बने। सर, मणिपुर में ग्रामीण क्षेत्र में 37,700 घर बन चुके हैं और अर्बन एरिया में 16,700 घर बन चुके हैं। और तो और, अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने 7,000 नए घरों के लिए sanction दिया है, इसलिए वहां पर और भी घर बनेंगे। सर, इन लोगों ने मणिपुर के बारे में बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन इनको सत्य बातें कहनी चाहिए, इसलिए मुझको लगा कि पहले मणिपुर की ही बात की जाए।

दूसरा, जो Appropriation Bill, 2024-25 है, उसमें अगर देखा जाए कि what is the total amount expenditure for which the Appropriation Bill has come? ...*(Interventions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interventions)*...

SHRI ARUN SINGH: It is for Rs.6.78 lakh crore, लेकिन उसमें से Rs.5.5 lakh crore is for the repayment of debt so that the high cost debt be repaid and this fund can be mobilized. Net cash outflow is just Rs.51,462 crore. 6.78 लाख करोड़ रुपए का जो सप्लीमेंट्री बिल आया है, net cash outflow is just Rs.51,462 crore, उसमें भी सबसे अधिक पैसा fertilizer subsidy के लिए खर्च हुआ है, क्योंकि यह मोदी सरकार है। किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है और किसानों के लिए जो भी मदद होती है, उसको वे एक कदम बढ़ कर करते हैं ताकि किसान को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. ...*(Interventions)*...

श्री अरुण सिंह : सर, fertilizer subsidy के लिए 14,100 करोड़ रुपए के लिए है ताकि किसानों को यूरिया और P2K पर सब्सिडी दी जा सके। हमारी सरकार में, चाहे वह कोविड का समय हो, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, यूरिया का इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों के fertilizer के दाम कभी भी नहीं बढ़ने दिए। आज वह 2,500 रुपए प्रति बोरी cost आती है, लेकिन उन्होंने केवल 242 रुपए में देने का काम किया है। इसी कारण आज किसान हमारे साथ हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interventions)*...

श्री अरुण सिंह : सर, हम 2024-25 में 'पीएम किसान योजना' के अंतर्गत 63,500 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं। 2024-25 में क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से भी 15,864 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया, ताकि किसान तकलीफ में न आए। किसान के लिए ब्याज दर भी सस्ता हो, किसान अधिक ब्याज दे नहीं सकता, इसलिए किसान को subvention दिया जाता है। अगर किसान समय पर पेमेंट करता है, तो उसको 4 परसेंट ही ब्याज लगेगी। 2024-25 में उसके लिए 22,600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है।

सर, इसी के कारण आज किसान हमारे साथ हैं। एक तरफ जहां एमएसपी का दाम बढ़ा है, वहीं इरिगेशन के एरिया को भी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जैसे अलग-अलग माध्यमों से बढ़ाने का काम किया गया है। मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसान के हितों से किसी भी प्रकार से कभी भी समझौता नहीं किया। अगर देश में सबसे ऊपर कोई है, तो वह अन्नदाता ही है और हम अन्नदाता की ही पूजा करते हैं, यही मोदी मंत्र है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas, do not speak while sitting. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... No; he is not addressing you. ...*(Interruptions)*... He is addressing the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री अरुण सिंह : सर, दूसरा विषय डिफेंस का है। हम कहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली भारत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, भारत के पास शक्ति होनी चाहिए। भारत में डिफेंस के लिए अगर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होगी, डिफेंस का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वह ठीक से नहीं होगा, हमारी सेनाओं के पास हथियार नहीं रहेंगे, तो हम कैसे शक्तिशाली हो सकते हैं? इसीलिए दूसरा सबसे अधिक पैसा इस सप्लीमेंट्री बिल में डिफेंस के लिए है। आज मैं बताना चाहूंगा कि हम डिफेंस में किस प्रकार से शक्तिशाली हो रहे हैं। 2014 का समय था, जब यूपीए के डिफेंस मंत्री कहते थे कि हम क्या करें, हम कोई रक्षा सामान खरीद नहीं सकते, क्योंकि I do not have the funds. 2014 में रक्षा की कोई procurement नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। उसी यूपीए के समय में आर्मी चीफ कहते थे कि क्या करें, हमारे पास गोली-बारूद नहीं है। अगर WAR हो गया, तो 10 दिन का भी हमारे पास गोली-बारूद नहीं है, क्योंकि हमारे

पास पैसा नहीं है। यूपीए के समय में यह स्थिति थी, डिफेंस से compromise किया गया। तब डिफेंस के लिए बजट भी नहीं था, फिर भी इतना kickback, इतना corruption था कि डिफेंस में corruption ही corruption था, जिसको सुन-सुनकर लोगों के कान भर जाते थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम डिफेंस को प्रॉयोरिटी देते हुए डिफेंस के इक्विपमेंट्स देश में बनाएंगे, industrial corridor देश में लगाएंगे। जब हमारे यहां talent pool है, हमारे यहां प्रतिभावान क्षमता के लोग हैं, हमारे पास संसाधन हैं, तो हम खुद क्यों नहीं डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, हम क्यों दूसरे पर डिपेंडेंट रहें? उसका नतीजा यह है कि आज डिफेंस की इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हो रहा है। यूपीए के समय में, वर्ष 2013-14 में डिफेंस में 686 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। आज प्रधान मंत्री मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। मतलब, 30 गुना अधिक डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है। 1,26,000 करोड़ रुपये की डिफेंस इक्विपमेंट्स यहां बन रही हैं। गोली-बारूद, सारी इक्विपमेंट्स, कलपुर्जे आज के दिन में यहां बन रहे हैं। डिफेंस का जो industrial corridor है, उसमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काम हो रहा है, उससे यह मान के चलिए और आने वाले समय में हमारा विजन है कि 2029 में 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का उत्पादन होगा। यह मोदी जी का मूल मंत्र है, इसको हम अवश्य ही अचीव करके रहेंगे।

सर, इसमें बहुत सारे Heads of Account हैं, लेकिन मैं यह जरूर बताऊंगा कि अगर आप पूरा देखेंगे, तो यह Bill गरीबों को समर्पित, किसानों को समर्पित और देश की infrastructure को समर्पित है। सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Shri G.C. Chandrashekhar; आप कन्नड़ में बोलेंगे। He will speak in Kannada.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, thank you for the opportunity to speak in my mother-tongue Kannada on the Appropriation Bills. At least, now, the Central Government remembered that there is a State by name 'Manipur' in the Indian map. After Independence, the most brutal and ethical war that took place during BJP Government was in Manipur. Till date, the Central Government is ignoring Manipur like anything. [&]"Sir, it is not just Manipur. A disturbing trend has emerged, where several States are being systematically ignored under this federal system. Every State holds deep respect, love, and trust toward the Central Government. That is why, in Karnataka's state anthem, we proudly sing, "Jaya Bharata Jananiya Tanujate, Jaya He Karnataka Maate!"—which means, "Victory to you, Karnataka, the daughter of Mother India. This showcases the immense respect Kannadigas have for the country; not only Karnataka, all the States have so much affection for the country. Yet, despite this devotion, the Central Government continues to treat some States like a

[&] English translation of the original speech delivered in Kannada.

caring mother while others are left neglected, like stepchildren. Karnataka, like Manipur, has been a victim of this injustice. I stand before you today to present the harsh reality using Karnataka as an example, and after hearing these facts, I will leave it to your judgment.

From 2017-18 to February 2024, Karnataka contributed nearly nine percent to the national GDP. It is the second highest tax-paying State in the country and leads in IT, biotechnology, and innovation. Despite this, the Central Government's policies have systematically weakened Karnataka's financial position. For the last five years, Karnataka was supposed to receive its rightful share of tax revenue, yet the Central Government withheld ₹1.65 lakh crore. Sir, that is not a small money for any State, it is a big money. When this money is not given, it is not so easy to run the state. This is not a minor shortfall. It is a significant amount, a lifeline that has been unjustly taken away from the state. Without this rightful share, it becomes increasingly difficult to run the state smoothly. How can a state function when the revenue it deserves is being held back?

Sir, the injustice Karnataka has faced is evident in multiple ways. Due to unscientific GST policies, the State suffered a loss of ₹59,274 crore. The 15th Finance Commission reduced Karnataka's tax share from 4.713% to 3.647%, leading to a loss of ₹65,000 crore over five years. The increase in cess and surcharges has further drained Karnataka's resources, causing a loss of ₹55,000 crore. In total, between 2018 and 2024, Karnataka has lost ₹1.65 lakh crore. Is this the fairness we expect in a federal structure? Karnataka has always fulfilled its duties, contributed to the national economy, and stood by the nation in times of need. Yet today, it is being systematically deprived of what it rightfully deserves.

While Karnataka's tax share has been shrinking, other States have seen substantial increases. In 2018-19, Karnataka received ₹35,894 crore as its share of central taxes. By 2023-24, this amount had dropped to ₹21,932 crore, resulting in a loss of ₹14,053 crore. Meanwhile, Uttar Pradesh's tax share increased from ₹1,36,766 crore to ₹1,83,238 crore, Bihar's share rose from ₹73,603 crore to ₹1,02,737 crore, and Gujarat, which had a tax share similar to Karnataka in 2018-19, saw its allocation increase by ₹12,036 crore—a 51 percent hike. Yet Karnataka, despite its economic contribution, faced an unprecedented reduction in its share. The situation does not end there. The financial constraints imposed on Karnataka have forced the State into massive debt. In 2018, Karnataka's debt stood at ₹2.45 lakh crore. By 2023, due to financial strain caused by the Central Government's unfair policies, this debt had skyrocketed to ₹5.40 lakh crore—an alarming 93 percent increase. Meanwhile, States like Uttar Pradesh, which required financial assistance, received it in the form of

grants rather than loans. Their debt increased by only 24 percent over five years, while Gujarat's debt rose by just ₹1 lakh crore because they received financial support through grants. Karnataka, on the other hand, was denied this relief and was instead pushed into borrowing.

During the financial years 2020-21 and 2021-22, instead of compensating Karnataka for GST shortfalls, the Central Government forced the State to take loans amounting to ₹30,000 crore. Even under Centrally sponsored schemes, Karnataka's funding has consistently declined. In 2019-20, Karnataka received ₹14,505 crore, but by 2023-24, this amount had dropped to just ₹11,269 crore—a sharp decline of ₹3,000 crore in just four years. At the same time, States like Uttar Pradesh received ₹2,67,774 crore, Madhya Pradesh received ₹1,57,399 crore, and Bihar received ₹1,28,541 crore in financial assistance. Karnataka is not objecting to these allocations. The question is, why is Karnataka being treated differently? Why is our rightful share being denied?

Karnataka has always stood with the nation. During the integration of princely states, Mysore, one of the richest princely states, voluntarily joined the Indian Union at the request of Sardar Vallabhbhai Patel. He believed that the financial strength of states like Mysore would help stabilize the newly independent nation. Today, that very state, which once symbolized economic stability, has been strategically weakened and burdened with debt. For the last five to six years, Karnataka has received zero in Special Assistance Grants. Karnataka has always fulfilled its duties, contributed to the national economy, and stood by the nation in times of need. Yet today, it is being systematically deprived of what it rightfully deserves. This is the price the state is paying for being one of the country's biggest contributors to GDP. I ask you, what has Karnataka done to deserve this? It is a state that contributes significantly to the nation's economy, a state that has never failed in its responsibilities toward India. Then why is Karnataka being treated as an outsider in its own country? Is this the federalism we believe in? Is this the justice we promised our people?

Beyond financial injustice, Karnataka is also facing a severe drought crisis, yet it has been deprived of much-needed relief. The National Rainfed Area Authority of India, in a report presented in this very session, confirmed that 24 districts in India are experiencing severe drought. Sixteen of these districts are in Karnataka. Despite this alarming situation, Karnataka has received little to no relief from the Central Government. The State suffered losses amounting to ₹35,162 crore due to drought between 2018 and 2023. Karnataka requested ₹18,000 crore in aid, but only ₹3,400 crore was released, and that too only after intervention from the Supreme Court. For the first time in the history, Sir, we went to the Supreme Court for relief. In a shocking

move, the Central Government then filed an affidavit stating it would provide no further assistance to Karnataka. As of January 2024, the Central Government still owes Karnataka ₹9,352.52 crore, including Rs. 200 crores pending in the Mid Day Meal Programme. Rs.1,429.33 crores is yet to be released for the National Rural Drinking Water Programme. Rs. 718 crores was announced for the Upper Bhadra project, but no funds have been given. ...*(Time-bell rings)*... Most importantly, from 2019 to 2020, by December 2024, Karnataka should have received Rs.20,400 crores under the Jal Jeevan Mission, Sir, but till today we have not received the fund. Sir, I leave you with these questions. Karnataka has given its best to this country. It now seeks what is rightfully its due."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, I will end with a poem of a great author, Shri D.V. Gundappa. That is most important. I will tell you.

&"Emperor, Empire, Gurukulas, religions, languages, and wisdoms have all vanished in the flood of time, but humanity still stands tall." – Mankuthimma. Sir, it means, "Nothing is permanent in this world; no power, nothing. The folk, culture, the great Emperor, Empire, Gurukulas, religions, languages, learnings will vanish over the night but humanity is forever."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, I will request the Central Government to show humanity towards other States. Then only can we grow. That is the thing. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, we grew up in school days reciting the National Pledge. I quote, "India is my country and all Indians are my brothers and sisters." But, today, I ask: Does this Government truly believe in these words? It is because if they did, they would have stood by the people of Manipur, they would have held their hands in the darkest hour, they would have wiped their tears, rebuilt their homes and

---

& English translation of the original speech delivered in Kannada.

restored their dignity. But what did they do instead? They abandoned them. They ditched them. They let down the people during the hard times. Since May 2023, due to ethnic violence, the situation has taken the shape of a civil war; and the same has not come to an end till today, even after a lapse of 22 months. When Manipur burned, when two women were paraded naked, sexually abused and tortured, and when homes were turned to ashes, when children cried for safety, when women were brutalized in most inhuman ways, where was our Prime Minister? He was not in Manipur. He was not with the people who desperately needed their leader. He was abroad, shaking hands, seeking votes, running election campaigns, but he did not have the time or courage to step foot in Manipur and say to its people, "I stand with you."

The entire State was cut-off from other States and no one was allowed to enter Manipur. There were no internet connections, no electricity, no water, no food. It almost took about 14 days to register even a zero-hour FIR for sexual assault and rape cases. And now they announced Rs. 400 crores for relief camps and Rs. 500 crores corpus to establish a contingent fund, that too after two years. They approved 7,000 houses with PM *Awas Yojana*. But tell me, can this money rebuild the lives of those who watched their homes go up in flames? Can it bring back the loved ones who were slaughtered in cold blood? Can it heal the wounds of women who were stripped of their dignity and paraded like objects in their own land?

The budget allocation is, in fact, inadequate to meet the concerns of more than 60,000 displaced people, the damages caused to life and property, for rehabilitation of the internally displaced persons, building of temporary shelters and housing for the displaced people. The truth of Manipur is this. More than 300 innocent lives have been lost; 249 churches were burnt down in just 36 hours after violence began. More than 400 churches have been destroyed till now. The estimated total damage is a staggering Rs. 20,000 crore, a sum greater than the meagre aid being handed out as a mere formality. The violence-hit Manipur has one of the highest rates of inflation and unemployment. There is growing restlessness and poverty. Unless the economy expands, none of these issues can be addressed. Bluster will not solve Manipur's pain. Mere acknowledgement will not heal its wounds. If you truly want peace in Manipur, then listen to the people of Manipur, not in closed door meetings, not in bureaucratic reports, but on the ground, in the streets, in their homes, amid the grief. Listen to their aspirations, their fear and their anguish. If you truly want peace, then, have the courage to face the truth, however inconvenient it may be. Let it be clear that this is not just a crime against the people of Manipur; it is a crime against humanity, against the very fabric of our nation. It is certainly not okay

for a Government that chants '*beti bachao beti padhao*', which means 'save the girl child, educate the girl child', to remain silent when the daughters of Manipur are being brutalised, raped and tortured. This is not a story of just one woman, this is not a tragedy of just one State; it is a stain on our nation's soul.

Sir, I would like to remind Madam Finance Minister that in the rupee note, the word '*rupai*' is there. Let me show it here. Therefore, there is nothing wrong in using the Tamil letter '*Ru*' in our Budget.

I would urge the hon. Finance Minister to be gracious enough to help Manipur come back to normalcy and make enough allocation for the State. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ghanshyam Tiwari; not present. Hon. Member, Shri Vaiko. Mr. Vaiko, your name is after Shri Ghanshyam Tiwari.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, Shri Wilson has donated three minutes of his time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, Sir. That is not the practice. Please speak on the subject.

SHRI VAIKO: Mr. Deputy Chairman, Sir, serious discussion is going on about Manipur and what is happening there. Rape, murder, arson, everything is going on. Hundreds of people have lost their lives. I have one simple question, a million dollar question – The Prime Minister of India is the custodian of 140 crore people. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, you cannot comment on the hon. Prime Minister. This will not go on record. ...*(Interruptions)*... It is a constitutional post... ...*(Interruptions)*... No, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Why did he not go to Manipur? He failed in his duty as... Prime Minister. Nobody will do that. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comment on his visit, please. It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Why, Sir? What is unparliamentary in that? ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your comments on the Prime Minister's foreign visit will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: What is unparliamentary in that? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा पर आप कुछ नहीं कह सकते। You may speak on the subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Sir, at the same time, the whole country is agitated on another issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may please speak. You are losing your time.

SHRI VAIKO: Prime Minister is 'PM'. * ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comments on... ...*(Interruptions)*... You know that he is on a constitutional post. You cannot comment like this. This will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: I have already said it and I would repeat it. I am not bothered about... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, speak on the subject. Only then it would go on record. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. You are losing your time.

SHRI VAIKO: Sir, you should be liberal. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to stick to the time limit. ...(*Interruptions*)... आप जानते हैं। ...(**व्यवधान**)... John Brittas *ji*, you take your seat. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAIKO: & "Our life and our prosperity are like our never fading Tamil. O , Conch, please blow the pride of our Tamil'. Which side will Hindi enter? How many regiments

---

* Not recorded

will Hindi bring? Our eyes may be torn. But we will slay and bury compulsory Hindi imposition." This is for anti-Hindi education. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAIKO: In Allahabad, some three months back, a conference was held by Hindu Mahasabha and hindutava forces. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak on the subject, please.

SHRI VAIKO: While speaking on the Appropriation Bill, you can speak anything under the sun. ...(*Interruptions*)... I have got the experience of 24 years in the Parliament. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAIKO: Mr. Deputy Chairman, ...(*Interruptions*)... While speaking on the Appropriation Bill, you can speak anything under the sun. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions)*...

SHRI VAIKO: The New Education Policy should be thrown into the ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)... I will call the next speaker. ...(*Interruptions*)... I am requesting you to conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAIKO: We are opposed to the New Education Policy. ...(*Interruptions*)... Our Dravidian model under our leader, Mr. Stalin ...(*Interruptions*)... *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)... I am calling the next speaker. ...(*Interruptions*)... You conclude or I am calling the next speaker. ...(*Interruptions*)... Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba ...(*Interruptions*)... आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... This is not going on record. You have

---

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

* Not recorded.

already taken more time. ...(*Interruptions*)... The Leader of the House wants to speak.

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : माननीय उपसभापति महोदय, हम सब लोग यहाँ वाद-विवाद, विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे वाइको साहब विभिन्न जिम्मेवारियों पर रहे हैं और लम्बे समय से संसदीय प्रणाली से अवगत हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि मणिपुर को छोड़ कर बाकी सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा की। दूसरी बात, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैं वही कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय जयराम जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा : दूसरी बात, उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी पर जिस तरीके से टिप्पणी की है, वह असंसदीय भी है और वह decency के बाहर भी है। ...(**व्यवधान**)... मुझे लगता है कि आप उसको examine कराएं और जो असंसदीय है और decency से बाहर है, उसे आप expunge कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told about it. ...(*Interruptions*)... जो भी असंसदीय चीजें या माननीय प्रधान मंत्री पर टिप्पणी होगी, उन्हें according to rules, we will examine.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on Manipur Budget 2025-26 and Manipur Appropriation Bill, 2025. At the very outset, I would like to thank hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi*ji* and hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitaramanji for the great concerns of my State, Manipur. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vaiko *ji*, nothing is going on record. Your time is over. You are wasting the time of the House. You are a senior Member. Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA: As Hon. Finance Minister on Monday, the 10th March, 2025, presented the Manipur Budget for the year 2025-26 in the Lok Sabha and today in Rajya Sabha, outlining a total expenditure of Rs.35,103.90 crore. ...(*Interruptions*)... The proposed Budget marks an increase from Rs.32,656.81

crore allocated in the previous fiscal year 2024-25. ...(*Interruptions*)... The total receipts have been pegged at Rs.35,368.19 crore, up from Rs.32,471.90 crore in 2024-25. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...(*Interruptions*).. He is wasting the time of the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA: As per the Budget documents, the capital outlay has been increased by 19 per cent to Rs.7,773 crore over the current financial year ending March, 2025. The Manipur's Budget provides for over Rs.2,000 crore under Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) and Rs.9,500 crore for Social Sector Outlay. A budgetary allocation of Rs.2,866 crore for 2025-26 has been made towards incentives for police personnel posted in the sensitive areas. The fiscal deficit is estimated at 3.42 per cent of the Gross State Domestic Product (GSDP), while the total outstanding debt is projected at 37 per cent of the GSDP. The allocations emphasize on relief, rehabilitation, infrastructure development, etc., aiming to stabilise the State's economy.

With the collective efforts of the Central and State Government, there has been improvement in the overall law and order situation in the State to a large extent. Except for some sporadic incidents in fringe areas and the incident on 8th March, 2025, in Kangpokpi, there has been a decreasing trend in cases of deaths, injuries, arsons, firing incidents, protests, etc.

Various measures have been taken up for the persons displaced by the violence. About 60,000 persons are currently residing in the relief camps. Around 7,000 persons have returned to their homes. Some of these measures include: (i) About Rs.400 crores have been provided under the Ministry of Home Affairs Special Package for Relief Camp Operations and support to those affected. I am glad to learn that more support is being provided. (ii) Under the Prime Minister Awas Yojana Grameen, 7,000 houses have been approved recently to provide for housing to those displaced persons. (iii) Various other supports have been given to those relief camps such as healthcare, including mental health support, skill and livelihood training, education, etc.

The Central Government has been extending continuous support to the State of Manipur during these challenging times. Apart from the support given for the Internally Displaced Persons, there is huge support in terms of security and law and order. Infrastructure development, vehicles, manpower, etc., have been provided by the Central Government. The border fencing project taken up by the Centre must be

expedited and completed on priority, as this project is essential for the security of our nation.

Various requests made by the State Government have also been agreed to by the Central Government. A Special Assistance Grant of Rs.500 crore was released to support the State in terms of the huge revenue loss suffered. Various relaxations regarding the Central Schemes were also provided, which gave relief to the State Government. The people of Manipur are confident that the support of the Central Government will continue. The economy of Manipur has suffered since the start of the unrest in May 2023. I request the Central Government to provide continued support for the State in terms of resources and projects. Being a small State, the resources invested in Manipur will not have much fiscal impact on the Centre but will have a large positive impact on the State.

As Manipur holds a strategic location by being the 'Gateway to East Asia', the State can contribute immensely to the economy and security of our country. For this to happen, the support of the Central Government is important and critical. I believe that this Budget will provide the necessary support to the State of Manipur.

I also express my thankfulness to my colleague, Hon'ble MP Dr. Ajeet Gopchade, for putting all the important facts about Manipur, but it is an undeniable fact that more than 60,000 displaced persons, including children and old-aged, are still taking shelter in different relief camps, facing the dire conditions for the last 22 months. They have no houses, no clothes, no property and nothing now. Their lives are about to start from zero. So, the continued support and help from the Central Government is highly needed. With these few words and humble demands for support of Manipur, I conclude my speech on the discussion on Manipur Budget 2025-26 and the Manipur Appropriation Bill, 2025. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Sandosh Kumar P. You have three minutes.

7.00 P.M.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, the need of the hour is to rebuild the State of Manipur and to reunite people's minds. But with the present Budget proposals and the approach of the Union Government, it is very difficult to achieve the target. Sir, Manipur is considered to be the jewel of our country and it is the land of great communist leader like Irabot. No work has started. I do not want to explain much because of paucity of time. Around 60,000 people were displaced, properties worth

20,000 crores of rupees were damaged and more than 300 people lost their lives. In fact, we do not know the exact data.

The point is that we have to rebuild the State of Manipur and think as to why the situation in Manipur reached to such a level. BJP, as a political party, should accept this fact that it was because of the failure of the BJP Government, both at the national level and at the State level, because of their approach, and, because of their misrule, situation in Manipur has reached to such a level. Now, it has become the lowest income generating State in the country and the fiscal liability of the State is 30 per cent of the Gross State Domestic Product.

During the 20 months of misrule, Manipur did not get any reasonable financial help from the Centre. To solve all these issues, what has to be done? This is the most important question. We stand with the people of Manipur. We have to solve this issue but the BJP and the hon. Prime Minister should re-visit their policies. The hon. Prime Minister was ready to visit zoo, the Prime Minister was ready to visit Mauritius. It is welcome. The hon. Prime Minister was ready to visit Ukraine. He even visited his close friend, Mr. Donald Trump but why did he not visit Manipur? As pointed out by many speakers here, one does not need to take permission to visit Manipur. Does he require any visa to visit the State of Manipur? Nothing is needed. Because of his calculated approach, he is not visiting Manipur. Moreover, clashes between people who live in hilly area and people living in valley area have to be resolved. For solving the problems of Manipur, we need a political solution and for that, the Union Government and the BJP leadership should adopt a new policy but this present policy of the Government will not help us in achieving peace in the State of Manipur. Thank you.

श्री उपसभापति : माननीय डा. सिकंदर कुमार, आपके 10 मिनट्स हैं।

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश) : सर, आपने मुझे The Appropriation Bill, 2025 and Vote on Accounts Bill, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार!

उपसभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में जो The Appropriation Bill, 2025 रखा है, इसमें डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के लिए मणिपुर हेतु जितने भी फाइनेंसियल प्रोविजंस किए गए हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, पिछले 10 वर्ष से मोदी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों और वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण हमारा देश लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं अभी अपने विपक्ष के मित्र को सुन रहा था। वे जो कह रहे थे, उनको सुनकर मुझे बड़ा अचंभा लगा कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। मान्यवर, देश की अर्थव्यवस्था तो तब मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जब हर दिन करोड़ों-

अरबों रुपए के घोटाले होते थे। आज तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हाथों में है। मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हाथों में इसलिए है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था, जो 11वें स्थान पर थी, वह अब पांचवें स्थान पर आ गई, तो यह मजबूत अर्थव्यवस्था का एक प्रमाण है।

हमने वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और वह बनेगी। इसलिए यह एक मज़बूत अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। ग्लोबल ग्रोथ रेट में आज भारत 15 परसेंट contribute कर रहा है और आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार 2028 तक यह योगदान 18 परसेंट तक पहुंच जाएगा। यह भी एक मज़बूत अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। गरीबी दर की बात करें, तो 2013-14 से पहले यह 29.1 परसेंट थी, जो अब घटकर 11.28 परसेंट रह गई है। यह भी हमारी बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। वर्ष 2014 से पहले हमारी Per capita income 86,454 रुपये थी, जो अब बढ़कर 2.7 लाख रुपये हो गई है। बैंकों का एनपीए 2014 से पहले 11 परसेंट था, जो अब घटकर 0.6 परसेंट रह गया है, यह भी हमारी बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रमाण है।

मान्यवर, हमारे विपक्षी मित्र बिना आंकड़ों के और राजनीतिक द्वेष के कारण टिप्पणियां करते हैं, लेकिन हमें तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। Exchange rate depreciation 6.3 परसेंट से घटकर 3.1 परसेंट रह गया है।

आज दुनिया की सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आज के दौर में सबसे बढ़िया इकोनॉमी यदि कोई है, तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था है। यह भी हमारी बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो...

श्री उपसभापति : डा. सिकंदर कुमार जी, आप बोलें। आपका माइक ऑन है।

डा. सिकंदर कुमार : एक समय था, जब हमारा देश International Monetary Fund और World Bank के पास लोन लेने गया, तब हमें वहां लोन देने से इंकार इसलिए किया, क्योंकि भारत के पास गिरवी रखने के लिए foreign exchange reserve नहीं था, लेकिन आज हमारा देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला देश बन गया है, जो 650 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।

मान्यवर, आज हम Manipur Appropriation Bill, 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। Central transfers to Manipur have increased substantially. अगर हम tax devolution को देखें, तो 2024 में जहां 9214.13 करोड़ था, जो अब बढ़कर 10,184 करोड़ रुपये हो गया है। हमारे विपक्ष के मित्र tax devolution की बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 2004-2014 के बीच यह 7,696 करोड़ था, जो 2014-2024 के बीच बढ़कर 46,312 करोड़ रुपये हो गया है, यानी इसमें 502 परसेंट की वृद्धि हुई है। अगर मणिपुर के लिए वर्ष 2004-2014 के बीच grants-in-aid from the Government of India देखें, तो 31,458 करोड़ रुपये से बढ़कर 76,303 करोड़ रुपये हो गई, यानी इसमें 143 परसेंट की वृद्धि हुई है।

मान्यवर, Special Assistance to States for capital investment to Manipur को देखें, तो 2021-22 में 213 crore रुपये से बढ़कर आज 987.13 करोड़ रुपये हो गई है। यह मैं आपके

माध्यम से बताना चाहता हूं। Since 2014, the Central Government has given significant attention to infrastructure development in each State, which is crucial to overall development. There have been efforts for infrastructure development in Manipur also. On 6th December, 2024, CCEA approved setting up 28 new Navodaya Vidyalayas in the uncovered districts, including 3 in Manipur. The Union Cabinet, on 7th March, 2024, approved Uttar-Poorva Transformative Industrialisation Scheme, 2024, that is, UNNATI, 2024, for a period of 10 years for development of industries and generation of employment in the North-East Region at a total cost of Rs. 10,037 crores. India's first ever national level sports university was set up in Manipur in 2018. New IIIT was inaugurated in Manipur in 2020. Imphal was selected under Smart Cities Mission. The North-East Special Infrastructure Development Scheme was approved during 2017-18, which continued to 2025-26 with two components, Road and Other than Road Infrastructure. Since inception, eight road and bridge projects worth over Rs. 375 crores have been approved for Manipur, and 235 Other than Road Infrastructure projects worth Rs. 2,411 crores have been approved for Manipur.

अगर हम रोडवेज़, रेलवेज़ को देखें, तो कई गुना 2014 के बाद सेंट्रल गर्वनमेंट ने मणिपुर को अस्सिटेंस दी है। The North-Eastern Region received record budgetary allocation for railway infrastructure projects. Annual average budget outlay for the North-Eastern Region 2009-14 was Rs.2,122 crore and now in 2025-26, it is Rs.10,440 crore. इसमें five times increase हुई है। There are ongoing projects and new tracks. Eighteen projects, 1,368 km of new tracks and 478 railway flyovers and underbridges have been constructed since 2014 by the Central Government. मान्यवर, गवर्नमेंट की अलग-अलग स्कीम्स हैं, मैं रिपिट नहीं करना चाहता हूं। अगर हम जन-धन अकाउंट देखें, तो पूरे देश में 54.3 करोड़ अकाउंट खुले हैं और मणिपुर में 11 लाख जन-धन अकाउंट खुले हैं। पीएम मुद्रा लोन पूरे देश में 31 लाख करोड़ distribute हुए हैं, तो मणिपुर में 2,850 करोड़ रुपये disburse किए गए हैं। StandUp India, जो पूरे देश में 30,600 करोड़ रुपये और मणिपुर में 57 करोड़ रुपये disburse हुए हैं। PM SVANidhi में 68 लाख street vendors को लाभ मिला है, उसमें 45 परसेंट वुमेन, 42 परसेंट ओबीसी और 23 परसेंट एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं और मणिपुर में 9,830 स्ट्रीट वेंडर्स को उसका लाभ मिला है। PM Vishwakarma के अंदर जहां पूरे देश में 2.64 लाख application sanction हुई है, मणिपुर में 438 application sanction हुई हैं। जन सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना में पूरे देश में 22 करोड़ लोगों की enrolment हुई है, मणिपुर में साढ़े तीन लाख लोगों की enrolment हुई है और Under the PM Awas Yojana – Gramin, the number of houses is 2.69 crore at all-India level whereas in Manipur 37,700 houses have been completed. Under the PM Awas Yojana – Urban, the figure is 90 lakh whereas in Manipur, 16,700 houses have been completed. मान्यवर, आयुष्मान भारत, ऑल इंडिया लेवल पर, जहां 36 करोड़ beneficiaries को लाभ मिला है, मणिपुर में 6.47 लाख beneficiaries को इसका लाभ मिला है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. SIKANDER KUMAR: I will take half a minute, Sir. जहां पूरे देश में 14,920 जन औषधि केन्द्र खुले हैं, वहां पर मणिपुर में 100 के लगभग केन्द्र खुले हैं। सर, मैं समझता हूं कि यह Appropriation Bill, 2025 मणिपुर के विकास को और गति देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसलिए मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए आप सभी से इस Appropriation Bill, 2025 का समर्थन करने की अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति : श्री रामजी लाल सुमन। आपके पास पांच मिनट का समय है।

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति महोदय, हम विनियोग विधेयक, 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बजट में किसी भी योजना के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा खर्च हुआ। अमूमन यह देखने में आता है कि जो बजट बनता है, उस बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है।

उपसभापति जी, भारत सरकार की जो योजना है, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ही एकमात्र तंत्र है। देखने में यह आता है कि राज्य सरकार कभी-कभी उस योजना में पैसा खर्च नहीं करती है। उस पैसे को दूसरी योजनाओं में खर्च कर दिया जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है।

उपसभापति जी, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए, जो यह देखे कि राज्य सरकारों को जो पैसा खर्च के लिए भेजा गया है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह तंत्र आज तक विकसित नहीं हुआ है। महोदय, इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि जो पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।

उपसभापति जी, कृषि के बारे में कहा गया है कि सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं और किसानों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, वे योजनाएं जमीन पर नहीं उतरीं। महोदय, खाद ब्लैक में मिलती है और ट्रैक्टर समेत जितने भी यंत्र हैं, उन सभी पर जीएसटी लगा हुआ है।

उपसभापति महोदय, मैं आज आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की फसल का जो नुकसान होता है, उसके बारे में सरकार ने कहा है कि हम किसान फसल बीमा करते हैं, लेकिन इस बार के बजट में किसान फसल बीमा राशि का जो आवंटन हुआ है, वह राशि बहुत कम है।

उपसभापति जी, जहां तक उत्तर भारत का सवाल है, उत्तर भारत में आवारा पशुओं का आतंक है और उसका परिणाम यह है कि जो आवारा पशु हैं, वे किसान के खेत को उजाड़ देते हैं, किसानों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे किसान मर जाता है।

महोदय, किसान की फसल का, किसान का जो नुकसान ये आवारा पशु करते हैं, उसके नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती है। महोदय, मैं आपसे दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब किसान खेती करने जाता है और जब ये आवारा पशु उस पर हमला करते हैं, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक 'किसान दुर्घटना बीमा योजना' चलती है। उसमें यह होता है कि यदि किसान काम करने के समय, खेती करने के समय मर जाता है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवारा पशुओं की वजह से जो किसान मारे जाते हैं, उनको भी 'किसान दुर्घटना बीमा योजना' में शामिल करना चाहिए।

उपसभापति जी, कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के लिए इस बार का जो बजट है, उस बजट में 80 परसेंट की कमी की गई है।

उपसभापति जी, हमारे देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और आज हिंदुस्तान में जो तनाव है, उस तनाव का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। सरकार को व्यवस्थित तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई नीति बनानी चाहिए, जिससे देश की बेरोजगारी हल हो सके। उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Jose K. Mani; three minutes.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, we stand here discussing numbers, allocations and financial plans but tell me, how can we talk about Budgets when the entire State of Manipur has been left abandoned, crying for help, unheard and unseen? How can we, as law-makers, sit in the comfort of this House when thousands in Manipur are living in fear, despair and hopelessness? With all respects, the hon. Prime Minister went all the way to Ukraine to express solidarity with war victims. There is nothing wrong in that. But, for Manipur, as a part of our nation, his schedule has no space. What message does it send to the people of Manipur? That their suffering is invisible; that their pain is not important. It is not about politics. It is about humanity.

Sir, Manipur has been burning for nearly two years. I had visited this place immediately after the violence and the disaster, and witnessed first-hand devastation and had spoken to the people. More than 500 people have lost their lives; more than 60,000 people have been displaced. We have seen that a lot of churches have been ransacked and deliberately destroyed to bring out violence to surface. Sir, what kind of *Viksit Bharat* are we building when our own citizens have become refugees in their own land? What kind of development are we talking about when Manipur, a proud State of this country, is still engulfed in fear and bloodshed? Will money alone heal

Manipur's wounds? We have seen budgetary allocations and announcement and financial packages. But will money bring back the lost lives? Will money erase the trauma of the mothers who saw their sons killed before their eyes? Will money rebuild the homes that were set on fire? No! Manipur does not need just money. It needs justice. It needs accountability. It needs action. So, let us not fool ourselves. Peace cannot be restored at gunpoint. Sending in more troops, imposing internet bans, and making hollow statements would not bring Manipur back to life. What will bring peace is political will, genuine dialogue and leadership that stands with the people, not away from them. Let me conclude. We demand answers, we demand action and we demand that this Government present a clear and time-bound plan for the safe return of displaced families and restoration of peace, and most importantly, justice for those who have suffered. Thank you for the opportunity, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Jose K. Mani*ji*. Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Tuesday, the 18th March, 2025.

The House then adjourned at twenty-one minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 18th March 2025.